छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

जिले का प्रथम दैनिक समाचार पत्र स्थापना वर्ष 2020

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | गौरेला पेंड्रा मरवाही, गुरुवार 01 अक्टूबर 2026 | वर्ष-07, अंक-92 पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

न्यूज इन शॉर्ट

रूस में नौकरी के नाम पर गए तेलंगाना के 4 युवक फंसे, परिवारों का दावा- रूसी सेना में भेजा गया



नई दिल्ली। तेलंगाना के चार युवकों के रूस में फंसने का मामला सामने आया है। परिवारों का आरोप है कि चारों युवक रूस में सिविलियन नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें रूसी सेना में सेवा के लिए भेज दिया गया। परिवारों का कहना है कि इनमें से कुछ युवकों को युद्ध क्षेत्र यानी यूक्रेन से लगी फ्रंटलाइन के करीब भी भेजा गया है। इससे उनके परिजन काफी चिंतित हैं। परिवारों ने तेलंगाना सरकार से हस्तक्षेप कर युवकों को सुरक्षित भारत वापस लाने की मांग की है। नौकरी का ऑफर मिलने के बाद रूस गए थे युवक परिवारों के मुताबिक, युवकों को रूस में सामान्य और मैकेनिकल हेल्पर जैसे 477 डॉलर मासिक वेतन और मुफ्त खाने की सुविधा का उल्लेख था।

1 करोड़ का इनामी आतंकी था हाशिम मूसा,शव मिला



नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर हाशिम मूसा उर्फ फौजी को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल की। तीन साल की तलाश के बाद बडगाम मेंकोकरनाग के जंगलों में उसका खात्मा हुआ। बुधवार सुबह पालमेदान इलाके में तलाशी के दौरान उसका शव मिला। पाकिस्तानी आतंकी मूसा शाहसितार और पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए भीषण नरसंहार का भी मास्टरमाइंड था।मूसा का नाम सबसे पहले बड़े आतंकी हमलों से 21 दिसंबर 2023 के ष्ठद्गह्लद्ब द्यद्ब त्नड्डद्यद्ब यानी ष्ठद्यत्न हमले के बाद जुड़ा। पुंछ-राजौरी के इस इलाके में आतंकियों ने सेना के वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए और 2 बुरी तरह घायल हुए थे।

2-8 अक्टूबर तक हर जिले में सेव डेमोक्रेसी मार्च- खरगे



नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन की बैठक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ष्टश्वष्ट ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे। एक नवंबर को विपक्ष की बड़ी रैली होगी।इंडिया गठबंधन की बैठक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यह बैठक साढ़े 3 घंटे तक चली। इसमें 20 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कुछ नेता वर्चुअली भी जुड़े। बहुत से नेताओं ने अपने विचार रखे। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी बात रखी। खरगे ने कहा कि मुझे खुशी है कि सभी ने ष्टश्वष्ट के खिलाफ मिलकर और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की बात की है। बहुत से सुझाव भी राहुल गांधी ने और ममता बनर्जी ने भी दिए हैं।

अरब सागर में नशे के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई



नई दिल्ली।अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल ने नशे के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात् अस् के साथ मिलकर चलाए गए ऑपरेशन में करीब 526 किलो हेरोइन और मेथामफेटामाइन जब्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 3 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस दौरान पांच पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है।जानकारी के मुताबिक खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तटरक्षक बल ने अरब सागर में लक्षद्वीप के पश्चिम में संदिग्ध नाव की निगरानी शुरू की।

साय कैबिनेट के 3 फैसले

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता अब और साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पुलिस, वन और जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10त्न आरक्षण लागू करने के नियमों को मंजूरी दे दी है।इसके साथ ही सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती और मानदेय से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने फिल्म 'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले से जुड़े आदेश को भी मंजूरी दी है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती के नियम तय

पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10त्न आरक्षण देने का फैसला पहले ही हो चुका था। अब इसे जमीन पर लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत पुलिस में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। नए नियमों में भर्ती का तरीका, पात्रता, चयन प्रक्रिया और सेवा शर्तें तय की गई हैं।

अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव को मिलेगा फायदा



अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव को भी मिलेगा महत्व

सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब मेरिट में दो अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अनुभव को भी मेरिट में जोड़ा गया है।एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने पढ़ाने पर 5 अंक मिलेंगे। अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक ही रहेंगे।

राज्य विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को भी उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर दोबारा नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। मानदेय की व्यवस्था में भी बदलाव होगा। अब इसे कालखंड के बजाय काम किए गए दिनों के आधार पर तय किया जाएगा।

'हनुमान अंश' के टिकट पर एसजीएसटी की भरपाई

कैबिनेट ने फिल्म 'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े आदेश को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।

इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने सिनेमाघरों को एसजीएसटी के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति करने का आदेश जारी किया था। कैबिनेट ने अब इस आदेश का अनुसमर्थन कर दिया है।

बिहार के सारण में गंडक पर बना बांध टूटा



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक समेत उत्तर बिहार की नदियां उफान पर हैं। 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इससे 1.59 लाख लोग प्रभावित हैं। बगहा-बेतिया में 4 जगह तटबंध टूटने के बाद बुधवार सुबह सारण में भी बांध टूट गया। निचले इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है। राज्य के 17 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ समेत पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों से मानसून लौट चुका है। इसके चलते प्रदेश में बारिश कम हो गई है।

हालांकि, पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश से घाघरा, सरयू समेत 8 से ज्यादा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को लखीमपुर में मंदिर 2 सेकंड में शारदा नदी में समा गया।

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के पडेरू में बारिश के बाद कई इलाकों में घना कोहरा दिखा। तापमान में भी गिरावट आई है। सुबह के समय लोग हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते देखे गए।

शाह बोले- दिल्ली शराब घोटाले वाले नशामुक्ति नहीं कर सकते



AAP ने पंजाब को चिट्टे में धकेला, 31 दिसंबर 2029 से पहले हम नशामुक्त कर देंगे

एजेंसी ➤ जालंधर

भगवंत मान ने नशे के व्यापार को और बढ़ाया है। नशे में गुरु का अपमान करने वाला नशामुक्ति नहीं कर सकता। जो दिल्ली में शराब बेचने के घोटाले में पकड़े गए हों, वे पंजाब को नशामुक्त कैसे करेंगे?शाह की रैली से पहले बम की धमकी भी मिली थी। कैंब्रिज स्कूल को भेजे ई-मेल में दावा किया गया कि रैली के स्टेज के नीचे ढ्ढश्वष्ठ रखा गया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में वहां कुछ नहीं मिला।

जवानों के लिए= आजादी से पहले का समय हो या बाद का, जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है, पंजाब का जवान सबसे पहले अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। आज भी जब सेना में जो बोले सो निहाल... का नारा लगता है, तो पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव भाग जाती है।

किसानों के लिए

देश में जब भी खाने-पीने की किल्लत या जरूरत पड़ी, पंजाब के किसानों ने कड़ी मेहनत कर हमेशा देश के अन्न भंडार को भरने का काम किया है। पंजाब सरकार ने किसानों को 26 फसलों पर स्क्क देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार उसे पूरा करने में विफल रही। इसके विपरीत, पड़ोसी राय हरियाणा ने अपने किसानों को फसलों पर स्क्कदे दी है। सरकार बनी तो किसानों के मुद्दे का परमानेंट हल करेंगे।

युवाओं के लिए= जब कुश्ती खेलने वाला देश का होनहार युवा नशे के कारण असमय मौत का शिकार होता है, तो बहुत दुख होता है। पंजाब के युवाओं से वादा है कि राय के सुनहरे भविष्य के लिए BJP को वोट दें, उन्हें नशे के इस दलदल से निकाल लेंगे। उन्हें रोजगार के उचित मौके देंगे।नशामुक्ति के लिए= भाजपा नशामुक्त पंजाब वादे को पूरा करेंगी। मैं खुद उन पीड़ित माताओं से मिलकर आया हूं, जिन्होंने नशे के कारण अपने बेटों को खो दिया। एक मां अपनी गोद में अपने 2 मृत बच्चों की तस्वीर लेकर पंजाब को बचाने की गुहार लगा रही थी।

पंजाब सरकार के लिए

पिछले 3 सालों में पंजाब सरकार ने एंटी-ड्रग्स की एक भी बैठक नहीं की। जालंधर में दफ्तर खोलने के केंद्र के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। आज पंजाब में महिलाओं क्बन चुकी है।

जिसे भाजपा सरकार आने पर

लगा मरने वाले हैं... चाकूबाजी, चीख और नीचे गिरता विमान,

ईरान के खिलाफ झूठा नैरेटिव, इजरायल जा रहे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

दुबई से इजरायल जा रहे प्लेन में सवार यात्रियों ने अपनी हैरान करने वाली कहानी बताई है। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने कॉकपिट में चीखने की आवाज सुनी तो पता चला कि वहां चाकूबाजी की घटना हुई है। यात्रियों ने कहा कि उन्होंने मिलकर हमलावर पर काबू पाया।

÷प्लेन का कंट्रोल बिगड़ने लगा, तो सभी लोग चिल्लाने लगे और उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं। कुछ मिनटों बाद, दो दूसरे पायलटों ने कंट्रोल



अपने हाथ में ले लिया। तभी कुछ इजरायली लोग एक आदमी की ओर दौड़े; उसने चाकू निकाला और पायलट को मारने की कोशिश की। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया।वहां चारों तरफ़ बहुत खून फैला हुआ था।÷हमने अब आतंकवादियों को काबू में कर लिया है। हम लैंड करने वाले हैं। जो कोई भी मेरी आवाज़ सुन सकता है, हमें मदद चाहिए। हम तबुक में नीचे उतर रहे हैं, जो शायद सऊदी अरब में कहीं है। एक अनजान और अपरिचित इलाका। पायलट को छोड़कर प्लेन में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। हमें मदद की ज़रूरत है।÷

हवा बिगड़ने से पहले की तैयारी

दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन अटैक से निपटने का प्लान सेट

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में अक्टूबर से पहले ही वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। इस बार कोशिश हवा खराब होने के इंतजार की नहीं उससे पहले शहर की तैयारियों की है।अक्टूबर आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा बिगड़ने लगती है। इस बार पॉल्यूशन बढ़ने का इंतजार करने की बजाय पहले से तैयारी शुरू हो गई है। सड़क की धूल से गाड़ियों के धुएं, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रियों और पराली तक ज्हर सोर्स पर एक साथ काम करने का प्लान है। सोचिए देखते देखते साफ हवा की समस्या इतनी विकराल हो गई कि सर्दियां आने से पहले ही पूरा सिस्टम एक्टिव करना पड़ रहा है।दिल्ली-एनसीआर की हवा कई चीजों से खराब होती है। सड़क पर जमा धूल, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का



अब सड़क की धूल पर मशीनों का वार

हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की बैठक में भी एनसीआर की हवा सुधारने की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसी के तहत यूपी के एनसीआर वाले 8 जिलों में मशीनों से डीप क्लीनिंगसे हटाने के बजाय मैकेनिकल मशीनों से साफ किया जाएगा ।

भारत-पाक सीमा के पास हाईवे बना रनवे, बीकानेर में सेना के रुद्र-ध्रुव और चेतक ने भरी उड़ान

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

राजस्थान के बीकानेर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब भारतीय सेना ने अपनी एयर ऑपरेशनल क्षमता और सैन्य गतिशीलता का प्रदर्शन किया। ह्म-911 के एक हिस्से को अस्थायी रनवे की तरह इस्तेमाल करते हुए सेना के हेलीकॉप्टरों रुद्र, ध्रुव और चेतक ने हाईवे से सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक-ऑफ किया।इस अभ्यास का मकसद यह दिखाना था कि जरूरत पड़ने पर पारंपरिक एयरबेस के अलावा हाईवे और दूसरे वैकल्पिक स्थानों से भी सैन्य हेलीकॉप्टर संचालित किए जा सकते हैं। अभ्यास के दौरान रुद्र, ध्रुव यानी.ग्र और चेतक हेलीकॉप्टरों ने हाईवे पर ऑपरेशन किया। रेगिस्तानी इलाके की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में की गई यह ट्रेनिंग सेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, एयर-ग्राउंड कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को मजबूत करने पर केंद्रित रही।सीमावर्ती इलाकों में ऐसे अभ्यास इसलिए अहम हैं, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में अगर मुख्य एयरबेस उपलब्ध न हो या वहां से ऑपरेशन करना संभव न हो, तो वैकल्पिक लैंडिंग जोन और सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना के मुताबिक, इस तामता को मजबूत किया जाता है।

'बैठक से पहले ही बिखर गया इंडिया गठबंधन', विपक्ष पर बरसे शिवराज सिंह

कांग्रेस अपनी गलतियों पर जनता से माफी मांगेंगे और आत्मचिंतन करेंगे

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बैठक से पहले ही गठबंधन बिखर गया, क्योंकि विपक्ष के कई बड़े नेता बैठक में शामिल ही नहीं हुए।एसआईआर (में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बुधवार को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। अब इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज इंडिया गठबंधन की



बैठक थी, लेकिन बैठक से पहले ही गठबंधन बिखर गया। यूपी में चुनाव है तो कहां हैं अखिलेश यादव, कहां हैं स्टालिन, कहां हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे वर्चुअली जुड़े और हेमंत सोरेन का अतापता नहीं।

शिवराज सिंह चौहान ने शायरी वाले अंदाज में कहा कि इंडिया गठबंधन की हालत ऐसी हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे।

शिवराज ने राहुल और खरगे पर साधा निशाना

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद देश ये सोचता था कि अपनी गलतियों पर जनता से माफी मांगेंगे और आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने तय कर रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। लगातार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खरगे हों या राहुल गांधी हों, अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं'।

उन्होंने कहा कि बैठक का नतीजा क्या निकला, शून्य विजन, हंड्रेड प्रेसेंट हताशा, चुनाव से पहले ही हार का बहाना। ये सेव डेमोक्रेसी के नाम पर सेव डायनेस्टी मार्च करना चाहते हैं 'परिवार बचाओ अभियान'।

न्यूज इन शॉर्ट



प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर देने 7 एवं 8 अक्टूबर को रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेला

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, /प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 7 एवं 8 अक्टूबर को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। रोजगार मेले में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की काउंसलिंग, मोबिलाइजेशन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा जिले की अग्रणी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का रोजगार हेतु पोर्टल पर अधिकतम पंजीयन कराया जाए। साथ ही पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों को 7 एवं 8 अक्टूबर को आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शामिल होने के लिए प्रेरित एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। मेले में शामिल होने वाले पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पिछले छह माह में जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों की संस्थावार जानकारी भी संकलित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं को जिला रोजगार अधिकारी से समन्वय कर ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की 8 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तरीय रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के साथ ही आईटीआई से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को विभिन्न नियोजकों के समक्ष अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

वीबी-जी राम जी योजना के तहत जिले के 163 ग्राम पंचायतों में बनेगी विकसित ग्राम पंचायत योजना

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जिले की 163 ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वीबी-जी राम जी योजना के तहत तैयार की जाने वाली इस योजना में ग्रामीण अपने गांव की जरूरतों, समस्याओं और विकास की प्राथमिकताएं तय करने में भागीदारी करेंगे। ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों, स्थानीय संसाधनों और क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर आगामी विकास कार्यों की योजना तैयार की जाएगी। योजना निर्माण की प्रक्रिया में ग्रामीणों को पंचायत से संबंधित आधारभूत आंकड़ों, मानचित्र और योजना तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार माह अक्टूबर और नवंबर में गांव एवं वार्ड स्तर पर बैठकें आयोजित कर ग्रामीणों से सुझाव लिए जाएंगे। दिसंबर में भूमि एवं क्षेत्र परिचय के आधार पर तैयार विकसित ग्राम पंचायत योजना का प्रारूप ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद योजनाओं को विकासखंड एवं जिला स्तर पर समेकित किया जाएगा। योजनाओं का समेकन 15 जनवरी तक पूरा किया जाएगा।

गैस की आपूर्ति सभी उपभोक्ताओं को सही ढंग से समय से दी जाएगी

एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने की वैकल्पिक व्यवस्था

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

जिले में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं सुचारू गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विगत कुछ दिनों में आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई जिससे उपभोक्ताओं को सुचारू गैस मिलने में किसी भी तरह की परेशानियां न झेलना पड़े । विगत कुछ समय से सियाराम गैस एजेंसी, गौरेला की सेवाओं एवं गैस वितरण को लेकर उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जनहित एवं उपभोक्ताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने



विगत कुछ दिनों में कुछ सुधारात्मक कार्यवाही की । इसके तहत सियाराम गैस एजेंसी से संबंधित उपभोक्ताओं की ऑनलाइन बुकिंग्स को आसपास की गौरेला पेंड्रा मरवाही के समीपस्थ गैस एजेंसियों में नियमित आधार में ट्रांसफर किया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को गैस मिलने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। बुकिंग्स के ट्रांसफर का मैसेज उपभोक्ताओं को कंपनी के द्वारा स्वचालित उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दिया जा रहा है। समीपस्थ गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि ट्रांसफर किए गए उपभोक्ताओं की बुकिंग स्वीकार करते हुए निर्धारित समय-सीमा में गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी सुनिश्चित करें। साथ ही उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को भी आवश्यकतानुसार आसपास के गैस एजेंसी में ट्रांसफर किया जा रहा है जिसका भी मैसेज कंपनी से स्वचालित रूप से उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। विगत कुछ दिनों में वैकलिप व्यवस्थाओं के करने से गैस की आपूर्ति सही ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचायी जा रहा है और आगे भी सही ढंग से जारी रहेगी। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वे किसी भी तरह की अववाहों में ध्यान न दें। गैस की आपूर्ति सभी उपभोक्ताओं को सही ढंग से समय से दी जाएगी।

प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा घरेलू गैस की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सुदृढ़ वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं और गैस सिलेंडरों का वितरण व्यवस्थित रूप से जारी रहेगा।

यदि किसी उपभोक्ता को गैस बुकिंग अथवा रिफिल प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो वे गैस कंपनी के राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कर्तव्य के प्रति लापरवाही पर व्याख्याता की संविदा सेवा समाप्त

लगातार अनुपस्थित रहने और नोटिस का जवाब नहीं देने पर की गई कार्रवाई

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

जिले में शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेण्ड्रा में पदस्थ व्याख्याता (अंग्रेजी) संविदा पायल कौशले की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मंगलवार को आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार पायल कौशले की नियुक्ति जिला स्तरीय चयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा व्याख्याता (अंग्रेजी) के अनारक्षित पद पर की गई थी। विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वे पूर्व में 20 दिसम्बर 2024 से 16 अगस्त 2026 तक लगातार कार्य से अनुपस्थित थीं। इसके बाद 17 अगस्त 2026 को विद्यालय में उपस्थित हुईं, किंतु 18 अगस्त 2026 से पुनः बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहीं।

लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता



से लेते हुए विद्यालय प्रबंधन द्वारा 25 अगस्त 2026 को नोटिस जारी किया गया, लेकिन संबंधित व्याख्याता द्वारा आदेश जारी होने तक नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए संविदा सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की है। आदेश में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के संविदा नियुक्ति संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि शासकीय कार्य के प्रति रुचि नहीं रखने तथा नियमित रूप से कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है। इसी प्रावधान के तहत व्याख्याता (अंग्रेजी) संविदा पायल कौशले को शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त/पृथक किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव : आकांक्षा पाण्डेय को अपर कलेक्टर और विक्रांत कुमार अंचल को एसडीएम पेण्ड्रारोड का प्रभार

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

राज्य शासन द्वारा जिले में पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण के फलस्वरूप कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नवीन प्रभार संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।

राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 सितम्बर को जारी आदेश के तहत जिले में पदस्थ श्री दिलेराम डाहिरे का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करते हुए उन्हें अपर कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है। श्री डाहिरे को नवीन पदस्थापना स्थल के लिए भारमुक्त किए जाने के पश्चात डिप्टी कलेक्टर सुश्री आकांक्षा पाण्डेय को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इसी तरह राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितम्बर के आदेश के तहत डिप्टी कलेक्टर श्री अमित बेक का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करते हुए डिप्टी कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है। श्री बेक को



भारमुक्त किए जाने के पश्चात डिप्टी कलेक्टर श्री विक्रांत कुमार अंचल को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेण्ड्रारोड का प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा गया है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत खाद्य विभाग का जनजागरूकता शिविर आयोजित

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,सेवा संकल्प अभियान के तहत खाद्य विभाग द्वारा सोमवार को विकासखंड मरवाही के ग्राम टिकठी में जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाना तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करना था। शिविर में उपस्थित नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं, उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण तथा खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। विभागीय अमले ने योजनाओं की पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में भी नागरिकों का मार्गदर्शन किया।इस अवसर पर आमजन को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक रहने तथा पात्रतानुसार उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी सीधे नागरिकों तक पहुंचाकर शासन और जनता के बीच संवाद एवं सेवा प्रदाय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।



एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को गैस की समस्या से राहत दिलाने प्रशासन और कंपनी ने किए ठोस पहल

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

जिले में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को सुचारू और समय से गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विगत कुछ दिनों में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई जिससे उपभोक्ताओं को एसपीजी गैस मिलने में किसी भी तरह की परेशानियां नहीं झेलना पड़े । जनहित एवं उपभोक्ताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विगत कुछ दिनों में सुधारात्मक कार्यवाही की। व्यवस्था में सुधार के तहत सियाराम गैस एजेंसी से संबंधित उपभोक्ताओं की ऑनलाइन बुकिंग्स को आस-पास की गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के समीपस्थ गैस एजेंसियों में नियमित आधार में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को गैस मिलने में



किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। बुकिंग्स के ट्रांसफर का मैसेज उपभोक्ताओं को कंपनी के द्वारा स्वचालित उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दिया जा रहा है। समीपस्थ गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि ट्रांसफर किए गए उपभोक्ताओं की बुकिंग स्वीकार करते हुए निर्धारित समय-सीमा में गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी सुनिश्चित करें। साथ ही उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को भी आवश्यकतानुसार आस-पास के गैस एजेंसी में ट्रांसफर किया जा रहा है जिसका भी मैसेज कंपनी से स्वचालित रूप से उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। विगत कुछ दिनों में वैकलिप व्यवस्था करने से गैस की आपूर्ति सही ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचायी जा रहा है और आगे भी सही ढंग से जारी रहेगी। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वे किसी भी तरह की अववाहों में ध्यान नहीं दें। गैस की आपूर्ति सभी उपभोक्ताओं को सही ढंग से समय पर दी जाएगी। प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा घरेलू गैस की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सुदृढ़ वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं और गैस सिलेंडरों का वितरण व्यवस्थित रूप से जारी रहेगा। अभी के समय में गैस आपूर्ति में कोई भी समस्या नहीं है और सभी उपभोक्ता किसी भी गलत अफवाहों का शिकार नहीं होएं। जिले में गैस की कोई भी समस्या नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को समय से गैस एजेंसी द्वारा गैस प्रदान सुनिश्चित किया जाएगा।

जल संरक्षण और भू-जल संवर्धन के लिए स्थानीय जरूरत के अनुरूप कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश

'धार अपार अभियान' : जिला पंचायत सीईओ ने घुड़देवा एवं नागधार नाला क्षेत्र का किया निरीक्षण

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

जिले में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू-जल संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित 'धार अपार अभियान' के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे ने सोन नदी की सहायक घुड़देवा नाला एवं नागधार नाला क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर जल संरक्षण एवं विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत अंडी, नगवाही, शिल्पहरी एवं लटकोनीखुर्द का दौरा कर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जल प्रवाह, उपलब्ध जल स्रोतों एवं जल संरक्षण की संभावनाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अमले को स्थानीय आवश्यकता और स्थल की उपयोगिता के आधार पर जल संरक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में नए तालाब, सामुदायिक कुएं, डबरी, छोटे चेक डैम, गैबियन स्ट्रक्चर, कंटूर ट्रेंच एवं रपटा सहित आवश्यक जल संरक्षण संरचनाओं के प्रस्ताव तैयार करने कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रस्ताव तैयार करते समय ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे वर्षा जल को अधिक से अधिक रोका जा सके और भू-जल स्तर में वृद्धि के साथ ग्रामीणों को दीर्घकालीन लाभ मिले।

जिला पंचायत सीईओ ने गोठान क्षेत्रों में औषधीय पौधों के रोपण पर भी



विशेष जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी एवं स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत मरवाही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पंचगण सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सेवा संकल्प अभियानः सौर ऊर्जा से सुशीला के घर रोशन हुई बचत की राह

पीएम सूर्य घर योजना से लगाया सोलर पैनल, 1.08 लाख की सब्सिडी मिली बिजली बिल हुआ लगभग शून्य

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

सेवा संकल्प अभियान के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों के जीवन में आए बदलावों की कहानियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़ निवासी सुशीला देवी के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बिजली खर्च में राहत का माध्यम बनी है। घर की छत पर सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल काफी कम होकर अब लगभग शून्य आ रहा है। सुशीला देवी ने बताया कि घर पर सोलर पैनल स्थापित कराने में करीब 1.95 लाख का खर्च आया। योजना के तहत केंद्र सरकार से 78 हजार और राज्य सरकार से 30 हजार की सहायता मिली। इस तरह कुल 1.08 लाख की सब्सिडी मिलने से



सोलर पैनल लगाने का आर्थिक बोझ काफी कम हो गया।

हर महीने बिजली खर्च में हो रही बचत

सोलर पैनल लगने से पहले सुशीला देवी के परिवार को नियमित बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। अब सौर ऊर्जा से घर की बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिल रही है और बिजली बिल लगभग शून्य आ रहा है। इससे परिवार को हर महीने होने वाले बिजली खर्च में बचत हो रही है। सुशीला देवी का कहना है कि सौर ऊर्जा अपनाने से उन्हें आर्थिक बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल का अवसर भी मिला है। योजना में मिली सब्सिडी के कारण उनके लिए घर पर सोलर पैनल लगाना आसान हो सका।

'सब्सिडी से आसान हुआ सौर ऊर्जा अपनाना'

सुशीला देवी ने योजना का लाभ मिलने पर प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से परिवार को बिजली खर्च में बड़ी राहत मिली है।

सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के अनुभव और उनके जीवन में आए बदलावों को सामने लाया जा रहा है। सुशीला देवी की कहानी भी इसी बदलाव की तस्वीर पेश करती है, जहां सरकारी सहायता और सौर ऊर्जा ने हर महीने के बिजली खर्च को बचत में बदलने में मदद की है।

न्यूज इन शॉर्ट

सेवा संकल्प अभियान में सामने आई सुनीता जायसवाल की सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की कहानी

एमसीबी सेवा संकल्प अभियान के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की कहानियां सामने आ रही हैं। इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ निवासी सुनीता जायसवाल की सौर ऊर्जा से जुड़ी कहानी सामने आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कराया है। सोलर पैनल लगने के बाद उनके बिजली बिल में काफी कमी आई है और वर्तमान में उनका बिजली बिल लगभग शून्य आ रहा है। सुनीता जायसवाल ने बताया कि उनके घर पर सोलर पैनल स्थापित करने में लगभग 2 लाख का खर्च आया। योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 78,000 तथा राज्य सरकार की ओर से 30,000, इस प्रकार कुल 1,08,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई। सब्सिडी मिलने से सोलर पैनल लगाने में होने वाला आर्थिक खर्च काफी कम हुआ और अब वे सौर ऊर्जा का लाभ उठा रही हैं।



उन्होंने बताया कि सोलर पैनल स्थापित होने के बाद बिजली के खर्च में उन्हें बड़ी राहत मिली है। पहले नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल लगभग शून्य आ रहा है। इससे परिवार को हर महीने बिजली खर्च में बचत हो रही है।

सुनीता जायसवाल ने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने से उन्हें आर्थिक लाभ के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का अवसर भी मिला है। योजना के माध्यम से मिली सब्सिडी ने उनके लिए सोलर पैनल लगाना आसान बनाया।

सुनीता जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से उनके जैसे परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिल रही है। उन्होंने योजना का लाभ मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के अनुभवों और उनके जीवन में आए बदलावों को सामने लाया जा रहा है। सुनीता जायसवाल की यह कहानी भी सौर ऊर्जा को अपनाने और बिजली खर्च में राहत मिलने की एक ऐसी ही लाभार्थी कहानी है।

दीपावली पर अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए 17 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

एमसीबी आगामी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अस्थायी पटाखा लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को 17 अक्टूबर 2026 तक लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित शुल्क एवं प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी पटाखा लाइसेंस के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों से निर्धारित अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है।

आवेदन कैसे करें-

अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदक अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक सेवा केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित शुल्क एवं शासन द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण- आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विलंब से आवेदन प्राप्त होने के कारण यदि लाइसेंस समय पर जारी नहीं हो पाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित आवेदकों से निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है।

योजनाओं का समेकन 15 जनवरी तक पूरा किया जाएगा

वीबी-जी राम जी योजना के तहत जिले के 163 ग्राम पंचायतों में बनेगी विकसित ग्राम पंचायत योजना

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही



जिले की 163 ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वीबी-जी राम जी योजना के तहत तैयार की जाने वाली इस योजना में ग्रामीण अपने गांव की जरूरतों, समस्याओं और विकास की प्राथमिकताएं तय करने में भागीदारी करेंगे। ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों, स्थानीय संसाधनों और क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर आगामी विकास कार्यों की योजना तैयार की जाएगी। योजना निर्माण की प्रक्रिया में ग्रामीणों को पंचायत से संबंधित आधारभूत आंकड़ों, मानचित्र और योजना तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार माह अक्टूबर और नवंबर में गांव एवं वार्ड स्तर पर बैठकें आयोजित कर ग्रामीणों से सुझाव लिए जाएंगे। दिसंबर में भूमि एवं क्षेत्र परिचय के आधार पर तैयार विकसित ग्राम पंचायत योजना का प्रारूप ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद योजनाओं को विकासखंड एवं जिला स्तर पर समेकित किया जाएगा। योजनाओं का समेकन 15 जनवरी तक पूरा किया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर खनिज विभाग ने की कार्रवाई, वसूला 50 हजार 578 रुपए का अर्थदंड



एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने मटियाडांड एवं मोहारीटोला क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से भंडारित लगभग 30 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की है। शिकायत के आधार पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच एवं निरीक्षण किया। जांच के दौरान शासकीय भूमि पर रेत का अवैध भंडारण पाया गया। इस पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। प्रकरण में संबंधित व्यक्ति पर 50 हजार 578 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। अर्थदंड की राशि निर्धारित खनिज मद में जमा कराए जाने के बाद प्रकरण का नियमानुसार प्रशमन किया गया। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों की गंभीरता एवं गुणवत्तापूर्वक जांच कर नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों पर सतत निगरानी रखते हुए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर रेल मंडल में 'सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर' आयोजित कर सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सामग्री का वितरण

रायपुर स्टेशन पर स्वच्छता कर्मियों की स्वास्थ्य जांच एवं रेलवे चिकित्सालय में स्वच्छता कर्मियों को पीपीई किट वितरण

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल में ÷स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत÷ थीम पर 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2026 तक स्वच्छता ही सेवा -2026 अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करना तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। इसी क्रम में 30 सितम्बर 2026 को ÷सफाई मित्र सुरक्षा, सेवा एवं सम्मान ÷ थीम के अंतर्गत रायपुर स्टेशन में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया ।

सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर –

सभी सफाई मित्रों के लिए मंडल के विभिन्न स्वास्थ्य इकाई एवं स्टेशन परिसर में सिंगल विंडो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य की व्यापक जांच सुनिश्चित की गई। शिविर में सफाई मित्रों के समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हुए विभिन्न आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। साथ ही सफाई मित्रों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, खान-पान में सुधार करने तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया गया।



पी पी ई किट एवं सुरक्षा सामग्री का वितरण –

'सफाई मित्र सुरक्षा, सेवा एवं सम्मान' थीम के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में सफाई मित्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे चिकित्सालय रायपुर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उन्हें पी पी ई किट एवं आवश्यक सुरक्षा सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें सेफ्टी ग्लव्स, मास्क, सेफ्टी जूते, रिफ्लेक्टिव जैकेट सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण शामिल रहे। इन सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से सफाई मित्रों को कार्यस्थल पर संभावित जोखिमों से बचाव के साथ सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सफाई मित्रों एवं स्वच्छताग्राहियों का सम्मान –

सफाई मित्र सुरक्षा, सेवा एवं सम्मान' थीम पर सफाई मित्रों एवं स्वच्छताग्राहियों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, अपने दायित्वों का समर्पण एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनके कार्यों की सराहना भी की गई ।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, सेतु मंडल रायपुर (छत्तीसगढ़)
ई–प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

दिनांक 29.09.2026

निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा "डी" श्रेणी एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों हेतु प्रथम निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 19.10.2026 तक है।

एन.आई.टी क्र./ निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
NIT NO. 33 Tender No. 200513	Painting Work of Curbs, Railings, Crarsh Barrier, Guard Stones and others of Various Bridges Under Sub Division Gaurela-Pendra-Marwahi and Mungeli.	रू. 17.16 लाख
NIT NO. 34 Tender No. 200515	Painting Works Of Kerb, Railing, Crash Barrier, Guard Stone And Other Painting Works On Various Bridges Under Bridge Construction Sub Division No.01 Bilaspur & Janjgir.	रू. 24.08 लाख
NIT NO. 35 Tender No. 200519	Special Repair Work Of Bituminous Concrete Wearing Coat For Various Bridges Under Bridge Construction Sub Division Gourella-Pendra-Marwahi.	रू. 16.40 लाख
NIT NO. 36 Tender No. 200525	Special Repair Work Of Bituminous Concrete Wearing Coat For Various Bridges Under Bridge Construction Sub Division Korba.	रू. 61.50 लाख
NIT NO. 37 Tender No. 200530	Painting Work of Kerb, Railing, Crarsh Barrier, Guard Stones and others of Various Bridges Under Sub Division Korba.	रू. 19.05 लाख
NIT NO. 38 Tender No. 200534	Special Repair Work Of Bituminous Concrete Wearing Coat For Various Bridges Under Bridge Construction Sub Division No.01 Bilaspur.	रू. 28.70 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ–पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम पर एनेक्जर–3 का शपथ पत्र, बिड केपेसीटी उपलब्धत्ता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेग, एवं निविदाकारो द्वारा प्रेषित मूल अभिलेख का लिफाफा में निविदाकारो का मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रुप से करें।

अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, सेतु मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

262703660/2

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

सेवा संकल्प अभियान : पकरिया जलाशय में गूंजा जल संरक्षण का संदेश

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज गौरेला विकासखंड के पकरिया जलाशय क्षेत्र में जल संरक्षण, जल स्त्रोतों की स्वच्छता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं पंचायत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जनजागरूकता रैली के साथ जलाशय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई की गई।जागरूकता रैली के माध्यम से ग्रामीणों को ÷जल है तो कल है÷ का संदेश देते हुए वर्षा जल के संरक्षण, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक जल स्त्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि जल संरक्षण केवल शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव और पानी के अपव्यय को रोककर जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।



कार्यक्रम के दौरान जलाशय एवं आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जल स्त्रोतों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही जलाशयों, तालाबों एवं अन्य पारंपरिक जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन में सामुदायिक सहभागिता के महत्व की जानकारी दी गई। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ जल स्त्रोत, सुरक्षित पेयजल और जल संरक्षण के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने भी जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखने, पानी का सदुपयोग करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाने में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लिया।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER,
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, (E/M) CIRCLE, BILASPUR (C.G.)
e-Procurement Tender Notice
Portal : http://eproc.cgstate.gov.in (Online)

Online Tenders are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh from contractors, C.G. P.W.D. in new Registraton System (Unified Registration System) for the following work : -

Sr.	NIT No.	Name of Work	PAC
1	NIT 83 200561 System Tender No.	Providing CCTV, Gyser, R.O., Pump, Water Cooler, TV and Other Electrification work at CG Bhawan Section Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	10.00
2	NIT 84 200563 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Residential and Non Residential Building at Chhattisgarh Bhawan Section Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	20.00
3	NIT 85 200564 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Residential and Non Residential Building at P.W.D. B./R. Division No. 02 Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	20.00
4	NIT 86 200567 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Rest House, Residential and Non Residential Building at Koni Section Under (E/M) Sub Division Bilaspur (C.G.)	19.85
5	NIT 87 200568 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Residential and Non Residential Building at Bahatarai Section Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	12.60
6	NIT 88 200569 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Rest House, Residential and Non Residential Building at Takhatpur Section Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	12.00
7	NIT 89 200573 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Rest House, Residential and Non Residential Building at Kota Section Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	15.90
8	NIT 90 200578 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Rest House, Residential and Non Residential Building at Masturi Section Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	12.55
9	NIT 91 200582 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Residential and Non Residential Building at P.W.D. B./R. Division No. 01 Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	19.80
10	NIT 92 200586 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Residential and Non Residential Building at Seepat Section Under (E/M) Sub Division Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)	19.30
11	NIT 93 200588 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Administrative Building Under (E/M) Sub Division G.P.M. Distt. G.P.M. (C.G.)	13.00
12	NIT 94 200589 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Residential Building at Gaurella and Marwahi Area Under (E/M) Sub Division G.P.M. Distt. G.P.M. (C.G.)	13.10
13	NIT 95 200594 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Non-Residential Building at Pendra Section Under (E/M) Sub Division G.P.M. Distt. G.P.M. (C.G.)	15.00
14	NIT 96 200598 System Tender No.	Providing Electrical and Air Conditioner Maintenance work in Non-Residential Building, Circuit House and Rest House at Gaurella-Pendra-Marwahi Section Under (E/M) Sub Division G.P.M. Distt. G.P.M. (C.G.)	15.00
15	NIT 97 200602 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Residential Building at Gaurella Section Under (E/M) Sub Division G.P.M. Distt. G.P.M. (C.G.)	16.00
16	NIT 98 200608 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Circuit house and Rest house Building at Mungeli, Lormi and Pathariya Section Under (E/M) Sub Division Mungeli Distt. Mungeli (C.G.)	15.00
17	NIT 99 200610 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Non Residential Building at Mungeli, Lormi and Pathariya Section Under E/M Sub Division Mungeli Distt. Mungeli (C.G.)	20.00
18	NIT 100 200611 System Tender No.	Providing Electrical Maintenance work in Residential Building at Mungeli, Lormi and Pathariya Section Under E/M Sub Division Mungeli Distt. Mungeli (C.G.)	18.00

(1st Call) Online Bid Submission 16.10.2026, Physical Document submission 23.10.2026

The Tender documents can be downloaded from the web-portal http://eproc.cgstate.gov.in only those contractors/bidders, interested in bidding shall pay the tender document const online.

262703665/5

Superintending Engineer
P.W.D. (E/M) Circle
Bilaspur (C.G.)

सेवा संकल्प अभियान में स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय

स्वास्थ्य मंत्री ने जरौंधा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया शुभारंभ, ग्रामीणों को अब स्थानीय स्तर पर मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

सशक्त एमसीबी सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई। छत्तीसगढ़ शासन के आयुष्मान आरोग्य मंदिर अंतर्गत जनपद पंचायत खड़गवां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरौंधा का शुभारंभ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत खड़गवां की अध्यक्ष श्रीमती श्याम बाई मरकाम ने की।



शुभारंभ समारोह में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ममता सिंह, जनपद पंचायत खड़गवां के उपाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह करियाम, जनपद सदस्य श्रीमती रामवती पोया एवं ग्राम पंचायत जरौंधा के सरपंच प्रदीप कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे, जिला पंचायत सदस्य रामजीत लकड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया।



इसके पश्चात रिबन काटकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरौंधा का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य केन्द्र के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सेवाओं का जायजा लिया।

सामान्य उपचार और स्वास्थ्य जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, सहज और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रारंभ होने से जरौंधा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा गांव के नजदीक उपलब्ध होने से ग्रामीणों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे समय और संसाधनों की बचत के साथ लोगों को आवश्यकता के समय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने के साथ ही लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

न्यूज इन शॉर्ट

कभी घर तक सीमित रहने वाली बसंती कश्यप अब बनीं लखपति दीदी

रायपुर। बस्तर जिले के विकासखण्ड बस्तर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुंड़ापाल की बसंती कश्यप ने साबित कर दिखाया है कि अगर सही नीति और दृढ़ संकल्प का साथ मिले, तो सफलता की नई इबारत लिखी जा सकती है। कभी घर की चारदीवारी और सामान्य कामकाज तक सीमित रहने वाली बसंती आज क्षेत्र में एक सफल लखपति दीदी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी विजन और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महिला सशक्तिकरण नीतियों को जाता है, जिन्होंने ग्रामीण अंचल की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है।

केंद्र और राय सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर विस्तार होने से जब बसंती गांव के महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं, तो उन्हें आजीविका संवारने के नए अवसर और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी मिली। समूह के माध्यम से मिले वित्तीय सहयोग और ऋण की मदद से उन्होंने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने इसके लिए एक व्यवस्थित शेड तैयार करवाया और उन्नत चूजे मंगाकर करीब दो से तीन महीनों तक उनका बेहतर प्रबंधन व पालन-पोषण किया। जब पहली बार मुर्गियों की बिक्री हुई, तो उन्हें उम्मीद से बढ़कर मुनाफा प्राप्त हुआ, जिसने उनके आत्मविश्वास को एक नई मजबूती दी।

इस मुनाफे को सहेजते हुए बसंती ने अपनी आमदनी को दोबारा उसी कारोबार में निवेश किया और पोल्ट्री फार्म का दायरा बढ़ाकर अपनी पारिवारिक आय को कई गुना कर लिया। अपने सपनों को साकार करने के बाद वे अब अपने पारा-मोहल्ले और समाज की अन्य महिलाओं को भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बसंती कश्यप की यह सफलता दर्शाती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के साझा प्रयासों से बस्तर के सुदूर अंचलों में मातृशक्ति स्वावलंबन और आर्थिक समृद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

सरकारी सहायता से आटा चक्की व्यवसाय को मिला विस्तार

रायपुर। किसी भी छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी और आधुनिक साधनों की अहम भूमिका होती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना ऐसे ही छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय सहायता और विस्तार का सुनहरा अवसर दे रही है। कोरबा जिले के तुमान निवासी अफराज अली ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने सामान्य आटा चक्की व्यवसाय को एक सफल और बड़े कारोबार में बदल दिया है। पहले अफराज अली के पास आटा चक्की का छोटा काम था, जिसके सीमित साधनों के कारण आमदनी का कोई स्थायी और मजबूत आधार नहीं था। जागरूकता शिविर से योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से आवेदन किया। इसके जरिए उन्हें 5 लाख रुपये का बैंक ऋण स्वीकृत हुआ, साथ ही 35 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ भी मिला। इस आर्थिक मदद से उन्होंने अपने व्यवसाय में आधुनिक तकनीक को जोड़ा और मशीनें खरीदीं, जिनमें नई आटा चक्की और हॉलर मिल, पैकिंग मशीन और वेजिंग मशीन, दाल चक्की मशीन की खरीदी कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया।आधुनिक मशीनें लगने से काम की रफ्तार और दायरा दोनों बढ़ गए हैं। अब आसपास के ग्रामीण धान, गेहूं और अन्य खाद्यान्न लेकर उनके पास आते हैं, जिससे उन्हें हर महीने करीब 25 से 30 हजार रुपये की आमदनी हो रही है। नियमित आय होने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे आसान किश्तों व किफायती ब्याज दरों पर बैंक ऋण का भुगतान भी कर रहे हैं। आज अफराज अली का यह व्यवसाय उनके परिवार की आजीविका का मजबूत सहारा बन चुका है। उन्होंने अपने काम को विस्तार देने में मिले इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर आमगांव में विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर



सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर आमगांव में विशेष नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

ग्रामीणों को गांव में ही जांच और उपचार की सुविधा

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकासखंड सूरजपुर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर आमगांव में विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आमगांव एवं आसपास के गांवों से पहुंचे लगभग 300 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श और निःशुल्क दवा वितरण का लाभ लिया। गांव में ही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से विशेष रूप से महिलाओं और वृद्धजनों को सुविधा मिली।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों की जांच की गई। सेक्टर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं सुपरवाइज़र के नेतृत्व में मरीजों के पंजीयन, जांच और परामर्श की व्यवस्था की गई ताकि ग्रामीणों को सुविधाजनक ढंग से सेवाओं का लाभ मिल सके।

शिविर में रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया एवं कुपोषण की जांच के साथ मुख, स्तन और गर्भाशय संबंधी कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। सर्दी, खांसी और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का परीक्षण कर उपचार दिया गया। महिलाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी प्रदान किया गया। टीबी के संदिग्ध मरीजों को आगे की जांच एवं आवश्यक नमूना परीक्षण के लिए रेफर किया गया। कुष्ठ रोग की जांच के दौरान चिन्हित संदिग्ध मरीजों को जिला अस्पताल सूरजपुर भेजा गया। नेत्र परीक्षण में मोतियाबिंद से प्रभावित पाए गए मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन एवं आगे के उपचार के लिए संबंधित उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया।

शिविर में स्वास्थ्य जांच के साथ ग्रामीणों को शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। पात्र हितग्राहियों के आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाया गया।



साथ ही 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड की जानकारी देकर ई-केवाईसी के माध्यम से कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड के उपयोग और उपचार प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संबंध में भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि जन औषधि केंद्रों पर किफायती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध होती हैं। शिविर में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं तथा उन्हें दवाइयों के नियमित सेवन एवं आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी साझा की गयी।

उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति की हुई अहम बैठक



उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम बैठक में हुए शामिल

16 प्रकरणों पर हुई प्रकरणवार समीक्षा, 9 प्रकरणों की हुई अनुशंसा

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी के संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह सुश्री निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि श्री मनीष ठाकुर, गृह सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, डीजीपी श्री अरूण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिसमें 8 लंबित प्रकरण शामिल थे, सभी मामलों में से 9 प्रकरणों की अनुशंसा की गई, 02 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए जिलों में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त शेष मामलों को राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ ना पाते हुए उनको समिति ने विचार कर उन्हें समिति ने अस्वीकृत कर दिया।

समिति ने अधिकारियों से पूर्व में अनुसंशित लंबित प्रकरणों, उनकी वर्तमान स्थिति तथा नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई एवं इसकी नियमित समीक्षा करते हुए न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।

आयुष योगा वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली को

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

आयुष विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, बौध्दिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु राय में वर्ष 2015 से 32 आयुष योगा वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य जन-जन तक योग की परंपरा को पहुँचाना तथा आधुनिक जीवनशैली में उत्पन्न तनाव, अवसाद एवं अस्वस्थता से मुक्ति दिलाना है।



राय के विभिन्न जिलों में संचालित योगा वेलनेस सेंटरों में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आहार परामर्श जैसी गतिविधियाँ नियमित रूप से कराई जा रही हैं। इन केन्द्रों में निःशुल्क नागरिकों को दैनिक योगाभ्यास की सुविधा दी जा रही है। योगा वेलनेस सेंटर न केवल स्वास्थ्य संवर्धन के केंद्र हैं बल्कि ÷रोग से मुक्त जीवन की ओर जनआंदोलन÷ के रूप में उभर रहे हैं। विभाग का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को योग से जोड़ना और ÷फिट इंडियाकी भावना को साकार करना है।

इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, दवाओं पर निर्भरता कम करने तथा मानसिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिल रहे हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर योग शिविर, कार्यशाला एवं विशेष अभियान भी आयोजित किए जाते हैं,।

2 अक्टूबर से गांव-गांव में 'रिफॉर्म उत्सव', ग्राम सभा से बनेगा विकास का रोडमैप

रिफॉर्म उत्सव के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) की प्लानिंग शुरू

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

पूरे छत्तीसगढ़ में 02 अक्टूबर 2026 से 'रिफॉर्म उत्सव' के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान (पीपीसी) के साथ एकीकृत रूप से आयोजित होने वाले इस अभियान में ग्राम सभाओं को गांव के विकास की प्राथमिकताएं तय करने और योजनाओं पर सीधे संवाद का प्रमुख मंच बनाया जाएगा। ग्रामीणों से उनकी जरूरतों, विकास की कमियों, उपलब्ध संसाधनों और जरूरी कार्यों पर सुझाव लेकर इन्हें ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा। रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में वीबी-जीरामजी के तहत 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी, 15 दिन में रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण साथ साथ लखपति दीदी योजना , आजीविका गतिविधि जैसे विषयों पर ग्रामीणों से संवाद होगा। पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

'ग्राम सभा से तय होगी विकास की प्राथमिकता'

वीजीपीपी के तहत 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में ग्रामीणों को योजना तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़ों, आधार मानचित्र और उपलब्ध अनुमेय कार्यों की जानकारी दी जाएगी। गांव में मौजूद लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं परिसंपत्तियों की पहचान भी की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में बस्ती और वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श के माध्यम से स्थानीय जरूरतों और विकास संबंधी कमियों की पहचान होगी। दिसंबर में तैयार वीजीपीपी का प्रारूप ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। ग्रामीणों के सुझाव और विचार-विमर्श के बाद ग्राम सभा योजना को अनुमोदित करेगी। इसके बाद योजनाओं का विकासखंड और जिला स्तर पर समेकन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी की जाएगी। वीजीपीपी में गांव की जरूरतों के अनुसार जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना,के प्रभाव को कम करने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

नई शुरुआत

सूरजपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों में गोद भराई, न्योता भोज और पोषण गतिविधियों में शामिल हुए

आंगन मिलन सेवा में सजी पौष्टिक थाली, घर-घर पहुंचा सुपोषण का

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों और परिवारों के बीच संवाद का माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में सूरजपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक थाली, न्योता भोज और विभिन्न गतिविधियों के जरिए स्वस्थ परिवार तथा सुपोषित बचपन का संदेश दिया गया। बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के साथ परिवार के सदस्यों ने भी कार्यक्रमों में भाग लिया।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में गर्भवती माताओं का स्वागत कर गोद भराई की रस्म संपन्न की गई। उन्हें पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और गर्भावस्था के दौरान आवश्यक देखभाल की जानकारी दी गई।

'मेरी पौष्टिक थाली' गतिविधि में चावल, दाल, हरी



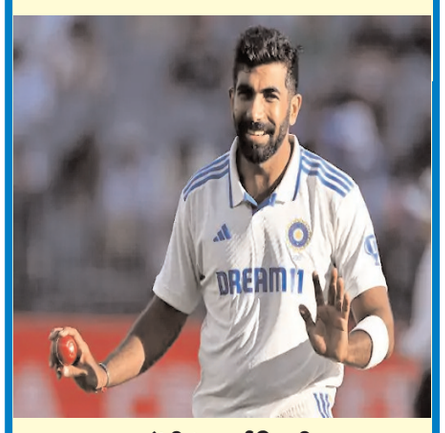
सब्जियों, मौसमी फलों और स्थानीय खाद्य पदार्थों से संतुलित भोजन तैयार करने का महत्व समझाया गया। पोषण संबंधी खेलों और व्यंजन गतिविधियों के जरिए महिलाओं को घर में उपलब्ध सामग्री से पौष्टिक भोजन बनाने के लिए प्रेरित किया गया। सामुदायिक सहभागिता से आयोजित न्योता भोज में बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसा गया। मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देने वाली मितानिनों को सम्मानित भी किया गया।



इस अवसर पर परिवारों को आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, बच्चों की वृद्धि निगरानी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा संबंधी सेवाओं की जानकारी दी गई। माताओं को बच्चों के वजन और पोषण स्तर की नियमित निगरानी तथा स्वच्छता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राहियों ने सहायता राशि से मिले लाभ के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिनों और परिवारों की सहभागिता से आंगन मिलन सेवा के माध्यम से पोषण की अच्छी आदतों को घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

न्यूजीलैंड टेस्ट से पहले सीनियर खिलाड़ियों को रणजी खेलना होगा



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वृष्टष्ठढ्ढ सीनियर भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए कह सकता है। खिलाड़ियों से कम से कम एक प्रथम श्रेणी मैच खेलने की उम्मीद की जा रही है।सान शुभमन गिल पंजाब और उप-कप्तान केएल राहुल कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह भी रेड-बॉल मैच में नजर आ सकते हैं।द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों के वर्कलोड और टीम की क्लीयरेंस के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। हाल में चोट से लौटे आकाश दीप और नितीश कुमार रेड्डी पर भी चयनकर्ताओं की नजर रहेगी।बुमराह के लिए लचीला रुख

बुमराह के वर्कलोड को देखते हुए वृष्टष्ठढ्ढ उन्हें रणजी ट्रॉफी या इंडिया-ए के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेलने का विकल्प दे सकता है। यानी उनके लिए घरेलू मैच का फॉर्मेट और संख्या फिटनेस के हिसाब से तय की जा सकती है।

फैसला 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के अनुभव के बाद आया है। उस सीरीज में भारत को 0-3 से हार मिली थी। बोर्ड इस बार न्यूजीलैंड दौरे से पहले खिलाड़ियों को पर्याप्त रेड-बॉल मैच प्रैक्टिस देना चाहता है।

19 नवंबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

भारत को न्यूजीलैंड में 19 नवंबर से दो टेस्ट की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अहम होगी। टीम के हालिया टेस्ट प्रदर्शन को देखते हुए नए सत्र में बेहतर तैयारी पर जोर दिया जा रहा है।

जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की



एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4म100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. नागोया में हुए फाइनल में किरण, प्राची, पूवामा माचेत्तिरा और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने जीत दर्ज की. स्वर्ण पदक जीतने के बाद चारों खिलाड़ियों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की

भारत को मिला 10वां गोल्ड



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 का 30 सितंबर यानी 11वां दिन शानदार रहा। आज भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कुराश, वॉलीबॉल, सेलिंग, सर्फिंग, टेनिस, स्क्वैश, कैनो स्लैलम, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग और साइकिलिंग की स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाया।

बुधवार यानी 30 सितंबर को आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया। भारत ने आज अब तक चार गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल कर ली है।चिकिथा, प्रितिका और योति सुरेखा वेन्नम ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके बाद एशियन गेम्स के मिक्स्ड कंपाउंड तीरंदाजी के खिताबी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने भी गोल्ड अपने नाम किया। आज के दिन भारत को तीरंदाजी से तीन तो वहीं शूटिंग में एक गोल्ड मेडल हासिल हुआ। ारत का कुश्ती अभियान भी आज से शुरू हुआ। महिला 68 किग्रा वर्ग में निशा दहिया को निराशा हाथ लगी। ग्रीको-रोमन 87 किग्रा में सुनील कुमार ने मुकाबला जीतकर ब्रॉन्ज हासिल कर लिया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक का फायदा मिला; गिल पहले, रोहित चौथे नंबर पर

कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की पारी खेली थी। इस पारी में पहली बार उन्होंने 9 छक्के लगाए थे। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की पारी खेली थी। इस पारी में पहली बार उन्होंने 9 छक्के लगाए थे।वराट कोहली ढ्ढष्ठ की वनडे बैटर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 139 रन की पारी खेलने का उन्हें फायदा मिला।कोहली के अब 796 रेटिंग पॉइंट हैं। वे टॉप पर मौजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल से सिर्फ 20 पॉइंट पीछे हैं। रैंकिंग हर हफ्ते बुधवार को जारी की जाती है।27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाए थे।



यह उनका वनडे करियर का 55वां शतक था। इसी पारी के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन भी पूरे किए। वह सचिन तेंदुलकर के बाद यह आंकड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। भारत ने मुकाबला 8 विकेट से जीता था।

टॉप-4 में 3 भारतीय बैटर्स

बैटर्स रैंकिंग के टॉप-4 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। शुभमन गिल ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया था। उन्होंने 110 रन की पारी खेली। इसके बाद गिल 816 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर-1 पर हैं। कोहली दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

कोहली ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़। वे 794 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत के रोहित शर्मा 753 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर हैं।

व्यापार

भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की दूरी

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन विदेशी निवेशकों का भरोसा उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो साल में करीब 40 अरब डॉलर की विदेशी पूंजी बाहर निकल चुकी है। बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, अब सिर्फ मजबूत वृष्टष्ठक्रग्रोथ विदेशी निवेशकों को भारत की ओर खींचने के लिए काफी नहीं है।भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन इसका असर विदेशी निवेशकों के रुख पर उसी तरह नहीं दिख रहा। देश की जीडीपी ग्रोथ मजबूत होने के बावजूद विदेशी



संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में पहले की तरह पैसा नहीं लगा रहे हैं। पिछले दो साल में भारतीय शेयरों से करीब 40 अरब डॉलर (?3।84 लाख करोड़) की विदेशी पूंजी बाहर निकल चुकी है।

ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन रिसर्च की 21 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले कुछ पुराने संकेत अब पहले जितने असरदार नहीं रह गए हैं।

सोना आज 712 और चांदी 673 महंगी

लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद रिकवरी; 10 ग्राम गोल्ड 1.48 लाख पारंग

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

सोने-चांदी की कीमतों में आज लगातार दो दिन की गिरावट के बाद तेजी है। इंडिया बुलियन एंड वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 712 रुपए बढ़कर 1,48,379 रुपए पर आ गया।इससे पहले 29 सितंबर को यह 1,47,667 रुपए पर था। वहीं, एक किलो चांदी 673 रुपए बढ़कर 2,22,273 रुपए पर आ गई है, जो मंगलवार को 2,21,600 रुपए पर थी।ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी-एक शहर से दूसरे शहर सोना ले जाने में ईंधन और सुरक्षा खर्च जुड़ता है, जिससे दूरी बढ़ने पर दाम बढ़ते हैं।

खरीदारी की मात्रा- दक्षिण भारत में यादा खपत (करीब 40त्न) के कारण वेलर्स बड़ी खरीद करते हैं, लेकिन छूट का फायदा सीमित रहता है।



लोकल वेलरी एसोसिएशन- राय और शहर के वेलरी एसोसिएशन स्थानीय मांग-सप्लाई के आधार पर रेट तय करते हैं।

पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य- वेलर्स का खरीदी रेट तय करता है कि वे ग्राहकों को कितनी कीमत में बेचेंगे।

सोना इस साल 15,180 महंगा और चांदी 8,147 गिरी

इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 15,180 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं, चांदी 8,147 रुपए सस्ती हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10द्द सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.48 लाख रुपए पर पहुंच गया है।

वहीं, चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.22 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई भी बनाया था।

:एपल पे भारत में लॉन्च, एक्सिस बैंक पहला पार्टनर बना; जानें- कैसे काम करेगा

आईफोन-एपल वॉच से बिना पिन-ओटीपी पेमेंट कर सकेंगे

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

एपल ने भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एपल पे को लॉन्च कर दिया है। साथ ही आईफोन और एपल वॉच यूजर्स के लिए कार्डलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का नया ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। इसके जरिए यूजर्स बिना पिन-ओटीपी पेमेंट कर सकेंगे।

एपल की इस सर्विस के लिए एक्सिस बैंक पहला पार्टनर बना है। शुरुआत में इसके तहत एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट दिया जा रहा है।कंपनी के मुताबिक, एपल पे के जरिए यूजर्स अपने एलिजिबल क्रेडिट कार्ड्स को एपल वॉलेट एप में जोड़कर खरीदारी कर सकेंगे।

भारत में शुरुआती फेज में यह सर्विस हजारों मर्चेंट्स पर अवेलेबल होगी। आने वाले समय में अन्य बैंकों, नेटवर्क और मर्चेंट एप्स को भी इससे जोड़ा जाएगा।



एक्सिस बैंक कार्ड को एपल वॉलेट से कैसे जोड़ें?

एक्सिस बैंक के एलिजिबल वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड होल्डर अपने कार्ड को एपल वॉलेट में आसानी से जोड़ सकते हैं। कार्ड जोड़ने के लिए यूजर्स एक्सिस बैंक एप के लेटेस्ट वर्जन या आईफोन में पहले से मौजूद वॉलेट एप का सहारा ले सकते हैं।

वॉलेट एप में कार्ड जोड़ने के लिए एप खोलकर प्लस साइन पर टैप और स्क्रीन पर दिख रहे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके बाद एपल पे सपोर्ट करने वाले मर्चेंट्स पर आसानी से पेमेंट किया जा सकेगा।

खास बात यह है कि एपल पे का यूज करने पर भी यूजर्स को उनके कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स और अन्य बेनिफिट्स पहले की तरह ही मिलते रहेंगे।

कैसे काम करता है और कौन इस्तेमाल कर सकता है?

अभी एप्पल पे की सुविधा सिर्फ एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ग्राहक अपने इन कार्ड को एप्पल पे में जोड़ सकते हैं। इसके बाद वे भारत में हजारों दुकानों, ऑनलाइन दुकानों और उन सभी जगहों पर भुगतान कर सकते हैं, जहां एनएफसी से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल पे और एप्पल वॉलेट की उपाध्यक्ष जेनिफर बेली ने भारत में एप्पल पे की शुरुआत को देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम बताया।

चैरिटी कमिश्नर तक पहुंची नोएल टाटा की शिकायत

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

नोएल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई, टाटा समूह की प्रमुख परोपकारी संस्थाओं टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन हैं। नोएल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई, टाटा समूह की प्रमुख परोपकारी संस्थाओं टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन हैं।टाटा ग्रुप में लीडरशिप और गवर्नेंस को लेकर विवाद बढ़ गया है। टाटा ट्रस्ट्स के जॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन ने सवाल उठाया कि नोएल टाटा चेयरमैन बने रहने के साथ-साथ ग्रुप की मुख्य ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी टाटा संस के मामलों में कैसे शामिल हो सकते हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, श्रीनिवासन ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर नोएल को हमेशा के लिए ट्रस्टी और चेयरमैन बनाए रखने पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा, उन्होंने नोएल के बेटे नेविल टाटा को ट्रस्टी बनाए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं।

श्रीनिवासन के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स अब समाजसेवा के अपने मुख्य काम से भटककर कंपनियों के बिजनेस फैसलों में दखल दे रहा है। ट्रस्टी खुद बड़े कारोबारी सौदों को तय करने, बातचीत करने और उन्हें फाइनल कराने में लगे हैं, जो कि चैरिटी ट्रस्ट के नियमों के खिलाफ है।

टाटा और श्रीनिवासन के बीच विवाद की 2 वजह

1. टाटा संस को शेयर बाजार में उतारा जाए या नहीं, इस पर दोनों के विचार अलग हैं। श्रीनिवासन चाहते हैं कि कंपनी बाजार में लिस्ट हो, जबकि नोएल टाटा इसके सख्त खिलाफ हैं।2. टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और उनके काम करने के तौर-तरीकों को लेकर भी दोनों के बीच मतभेद हैं।

विवाद इतना गहरा गया कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने वेणु श्रीनिवासन को टाटा संस की बोर्ड बैठकों में हिस्सा लेने और वोट डालने से रोकने का प्रयास किया।



मंत्री मारे थप्पड़

यह लोकतंत्र है या कोई गुंडा-मवाली राज है? क्या कोई मंत्री, जनता के बीच, शिकायतों के माहौल में, किसी युवक को सरेआम थप्पड़ मार सकता है? क्या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मंत्री के सामने, मंत्री के परिवार को, गालियां देने का दुस्साहस कर सकता है? दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने आवेश में आकर एक युवक को थप्पड़ मारा है। यह संज्ञेय और दंडनीय अपराध है, लेकिन चौतरफा राजनीतिक दबाव के बाद पुलिस ने शिकायत तो दर्ज की है, लेकिन वह 'गैर-संज्ञेय अपराध सूचना' (एनसीआर) ही है, जो महज खानापूर्ति है। आम आदमी पार्टी (आप) के जिस विधायक जरनैल सिंह ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की परतें उखाड़ कर मंत्री जी के सामने सब कुछ बेपरदा कर दिया था, उनके खिलाफ भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मंत्री ने विधायक पर ही 50 लाख रुपए की 'कमीशन' मांगने का आरोप चस्पां कर दिया है और विभाग के इंजीनियर से पुलिस में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। वह प्राथमिकी है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। मंत्री प्रवेश वर्मा की सफाई है कि जब इंजीनियर और ठेकेदार ने 'घूस' देने से साफ इंकार कर दिया, तो 'आप' विधायक ने सड़क उखाड़ कर साबित करने की कोशिश की कि देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता 'खस्ताहाल' है। मंत्री जी! आप झूठ बयां कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मॉनसून की बारिश सारी पोल खोल देती है। सड़कों की गुणवत्ता ही 'खस्ताहाल' नहीं है, बल्कि गहरे, खुले गड्ढे भी हैं, जो 'मौत के कुएं' साबित हो रहे हैं। और फिर विधायक जरनैल सिंह ने अपने हाथों से सड़क के टुकड़े उखाड़ कर मंत्री के सामने रखे थे,उन पर संबद्ध अधिकारियों और ठेकेदार को तलब क्यों नहीं किया गया? इंजीनियर को तुरंत निलंबित क्यों नहीं किया गया? विधायक ने तो काले, कुरूप सच को नंगा कर दिया था। क्या दिल्ली सरकार ऐसे ठेकेदारों को भी संरक्षण दे रही है?

(एक नजर)

10 दिन बाद नक्षत्र बदलेंगे शनि!

वैदिक योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना गया है. शनि ग्रह जब भी अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर काफी गहरा और दीर्घकालिक होता है. योतिषीय गणनाओं के अनुसार, साल 2026 में 9 अक्टूबर 2026 को शनि देव का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन उत्तर भाद्रपद शनि देव का अपना ही नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इस नक्षत्र में शनि का प्रवेश अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी साबित होगा. शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं. ऐसे में जब शनि का नक्षत्र गोचर होता है, तो वर्षों से अटके काम गति पकड़ने लगते हैं. शनि के इस महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन का असर यूं तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि 9 अक्टूबर के इस नक्षत्र गोचर से किन राशियों को करियर, बिजनेस और धन के मामले में जबरदस्त सफलता मिलने वाली हैवृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिनके साथ शनि देव का मित्रवत संबंध है. 9 अक्टूबर के बाद आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और बड़े पद का लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे।

विचार

शक्ति संतुलन, कूटनीति और जलवायु संकट

विकेश कुमार बडोला

लेकरव

जब तक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों- अमरीका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के देशज हित सधते रहे, तब तक महासभा का आयोजन शेष विश्व के लिए एक साधारण आयोजन हुआ करता था। किंतु जब से उक्त पांच देशों के मध्य स्वार्थ साधने एवं शीर्ष पर स्थापित होने की स्पर्धा बढ़ी तथा इनके प्रतिस्पर्द्धी बनकर दुनिया के कुछ अन्य देश भी खड़े हुए हैं, तब से महासभा की वार्षिक बैठक आरोप-प्रत्यारोप का मंच बन गई है। पांच देशों के प्रतिस्पर्द्धी बनकर खड़े होने वाले देशों में सम्मिलित हैं भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया।

प्रत्येक वर्ष किसी न किसी ऋतु में कोई न कोई प्रतिकूल संकटजन्य ऋतुगत घटना हो ही रही है। इस सत्य को सम्मुख रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और विशेषकर विकसित सदस्य देशों को जीवन-जगत के संबंध में मानवीय एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण अंगीकार करना होगाविश्व में अनेक स्तर पर हो रहे युद्धों, दो या अधिक देशों के पारस्परिक सशस्त्र संघर्षों तथा अन्य राजनीतिक प्रतिकूलताओं व नकारात्मक प्रतिस्पर्द्धाओं के बीच संपन्न संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक महासभा में अत्यधिक हलचल रही। सन् 2014 के बाद महासभा में ऐसी हलचल प्रत्येक वर्ष हो रही है और आगामी वर्ष में तीव्र से तीव्रतम हो रही है। जब तक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों- अमरीका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के देशज हित सधते रहे, तब तक महासभा का आयोजन शेष विश्व के लिए एक साधारण आयोजन हुआ करता था। किंतु जब से उक्त पांच देशों के मध्य स्वार्थ साधने एवं शीर्ष पर स्थापित होने की स्पर्धा बढ़ी तथा इनके प्रतिस्पर्द्धी बनकर दुनिया के कुछ अन्य देश भी खड़े हुए हैं, तब से महासभा की वार्षिक बैठक आरोप-प्रत्यारोप का मंच बन गई है। पांच देशों के प्रतिस्पर्द्धी बनकर खड़े होने वाले देशों में सम्मिलित हैं भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। विशेषकर भारत में 2014 के बाद जो शासन तंत्र स्थापित हुआ और जिस प्रकार स्वदेशी गौरव के प्रति एक तीव्र शासकीय एवं लोकतांत्रिक हलचल होनी आरंभ हुई, उस परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र के प्रभुत्व में दबदबा बनाए रखने वाले प्रमुख पांच देशों में से अमरीका, चीन एवं ब्रिटेन को कुछ अधिक बेचैनी हो गई है। भारत, रूस एवं चीन के नेतृत्व में ब्रिक्स सहित दक्षिण एशियाई एवं मध्य पूर्वी देशों के बीच अमरीकी-यूरोपीय शासकीय प्रभुत्व को खंडित करने के लिए वैचारिक एवं व्यावहारिक स्तर पर



जो नवचेतना जागृत हुई है, उसने भी विश्व को पिछले एक-डेढ़ दशक में पहले तो शीतयुद्ध में धकेला और अब उस कारण धीरे-धीरे विभिन्न स्तरों पर देशों के मध्य सशस्त्र संघर्ष भी बढ़ रहा है।जिस प्रकार विश्व समय-समय पर शीतयुद्ध से प्रभावित रहा है, उसी प्रकार भारत के केंद्रीय कल्याणकारी भूमिका में अवतरित होने के बाद संपूर्ण विश्व में शीत-समन्वय की धारणा जड़ें जमा रही है। अघोषित रूप से भारत की विदेश नीति सर्वमान्य हो रही है। विदेशों में भारत के मानवतावादी सिद्धांत की प्रशंसा हो रही है। किसी भी मंच पर भारत का मत स्वार्थ से विलग जगहित के लिए होता है। इस भाव को दुनिया के अधिसंख्य देश पहचान रहे हैं। भारत के शत्रु देश भी इस भावना से भलीभांति परिचित हैं। इसीलिए वे भारतीय पराभव के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त हैं। महासभा के मंच पर जहां अधिसंख्य देशों एवं उनके प्रमुखों तथा प्रमुखों की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों ने अपने-अपने हितों के रक्षार्थ भाषण किया तथा अपने शत्रु देश के प्रति आक्रोश से भरकर अपनी-अपनी आपत्तियां प्रकट कीं, वहीं भारतीय प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अत्यंत शांत होकर, संयम एवं विनीत भावना के साथ वैश्विक युद्धजन्य संघर्षों, प्राकृतिक चुनौतियों, असमान सुख-सुविधाओं के वितरण, आदि मानवीयता-केंद्रित विषयों पर संभाषण किया तथा पारस्परिक सेवा व सहयोग के विचार के साथ विकसित होने के विचार पर बल दिया। हालांकि उन्होंने भी भारत के पारंपरिक शत्रु देश पाकिस्तान पर मंच से दोषारोपण किया, किंतु ऐसा आरोप कल्पना आधारित नहीं है। यह अनेक स्तर पर प्रामाणिक है। यह अलग बात है कि न तो अमरीका और न ही संयुक्त राष्ट्र ने इस पर आज तक गंभीरतापूर्वक विचार किया है।

विचार

पारदर्शिता की राह में स्वायत्तता का सवाल

डा. सतपाल

लेखक

इस विधेयक के तहत राय के अंतर्गत छह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार का हालिया फैसला केवल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का विषय नहीं है, बल्कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही के बीच संतुलन का भी प्रश्न है। सरकार का तर्क है कि सरकारी धन से चलने वाले विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह होनी चाहिए।

सवाल यह नहीं होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग अच्छा है या विश्वविद्यालय की चयन समिति। असली सवाल यह होना चाहिए कि हिमाचल को सबसे योग्य शिक्षक किस व्यवस्था से मिलेंगे और उस व्यवस्था में पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित होगीहिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश राय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 को विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित कर दिया है। इसकी वास्तविक प्रभावशीलता अब माननीय रायपाल महोदय की स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगी। इस विधेयक के तहत राय के अंतर्गत छह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार का हालिया फैसला केवल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का विषय नहीं है, बल्कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही के बीच संतुलन का भी प्रश्न है। सरकार का तर्क है कि सरकारी धन से चलने वाले विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह होनी चाहिए। दूसरी ओर, विश्वविद्यालयों के भीतर यह चिंता स्वाभाविक है कि यदि शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सरकारी भर्ती व्यवस्था के अधीन कर दी जाती है, तो इससे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। क्या पारदर्शिता और स्वायत्तता एक-दूसरे की विरोधी हैं, या दोनों को साथ लेकर चलने वाली कोई बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है।यही इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विधानमंडल के अधिनियम के तहत हुई। यह प्रदेश का सबसे पुराना प्रमुख बहुविषयक विश्वविद्यालय है। इसके बाद राय की विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप कई विशिष्ट विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में, नौणी में डा. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की 1985 में, हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की 2010 में, नेरचौक में अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की 2018 में तथा मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में हुई। स्पष्ट है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी विशिष्ट शैक्षणिक भूमिका और आवश्यकताएं हैं। ऐसे में सभी के लिए



एक समान भर्ती व्यवस्था लागू करना कितना उचित होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों की व्यवस्था पहले से मौजूद है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार भी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विषय विशेषज्ञों और शैक्षणिक प्रतिनिधियों वाली चयन समितियों की व्यवस्था की गई है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि विश्वविद्यालयों में अब तक नियुक्तियां किसी नियम-कायदे के बिना होती रही हैं। विश्वविद्यालयों के पास अपनी वैधानिक चयन व्यवस्था रही है और नियुक्तियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं तथा चयन प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित रहा है। अन्य विश्वविद्यालय की तरह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अपनी भर्ती शाखा और चयन प्रक्रिया भी लंबे समय से अस्तित्व में रही है। यह भी विचारणीय है कि प्रदेश विश्विद्यालयों की शिक्षक भर्तियों के साथ-साथ राय आयोग की भर्तियां भी कटघरे में रही हैं। वर्तमान में शायद इस फैसले की पृष्ठभूमि में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्तियों से जुड़ी आपत्तियां भी महत्वपूर्ण हैं।वर्ष 2020 से 2023 के बीच हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियां हुईं जिन्हें महालेखा परीक्षक ने शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के पर्याप्त सत्यापन अभिलेख उपलब्ध न होने पर सवाल उठाए तथा कुछ मामलों में पात्रता संबंधी अनियमितताएं भी चिन्हित कीं। लेकिन महालेखा परीक्षक ने नियुक्तियों को अवैध घोषित नहीं किया अपितु रिपोर्ट का मुख्य जोर प्रक्रिया, अभिलेखों और प्रमाणपत्रों के सत्यापन की कमी पर था। इसलिए इस रिपोर्ट को आधार बनाकर विश्वविद्यालय की प्रत्येक नियुक्ति पर प्रश्नचिह्न लगाना न तो उचित होगा और न ही तथ्यपरक। यदि किसी नियुक्ति प्रक्रिया में प्रमाणपत्रों का विधिवत सत्यापन नहीं हुआ, चयन प्रक्रिया के अभिलेख पूरे नहीं हैं या पात्रता की जांच में कमी रह गई है, तो व्यवस्था को सुधारना आवश्यक है। सरकारी धन से चलने वाले किसी भी संस्थान में नियुक्ति प्रक्रिया इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बाद में किसी को उस पर उंगली उठाने का अवसर ही न मिले। विश्वविद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति सामान्य सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति से अलग होती है। किसी प्रशासनिक पद के लिए सामान्य परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया पर्याप्त हो सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय में शिक्षक केवल एक कर्मचारी नहीं होता। वह अध्यापन, अनुसंधान, मार्गदर्शन और अकादमिक नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए किसी शिक्षक का चयन केवल सामान्य भर्ती प्रक्रिया से नहीं, बल्कि उसके विषय ज्ञान, शोध कार्य, प्रकाशनों, अध्यापन क्षमता और संबंधित वाले विशेषज्ञों द्वारा होना चाहिए।

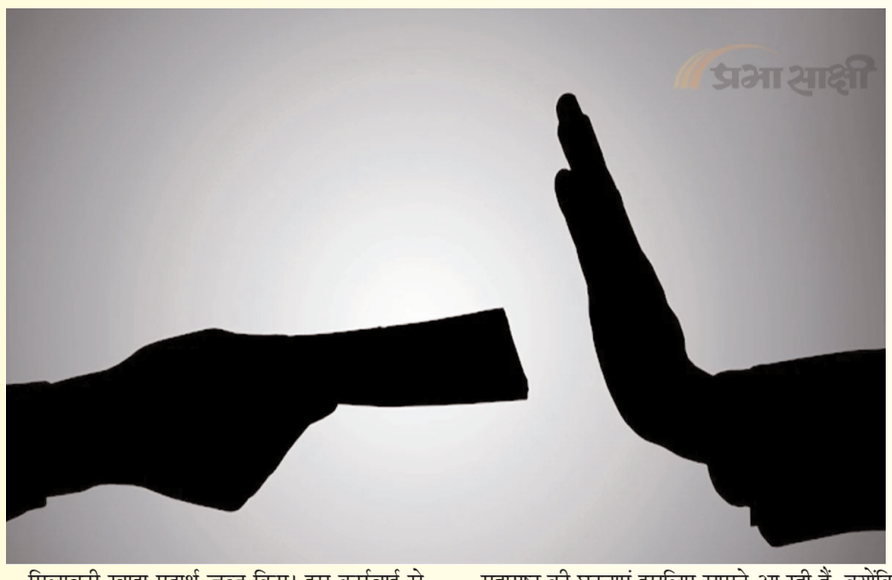
विचार

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मिलावटखोरी रोकने की व्यवस्था

उमेश चतुर्वेदी

लेखक

महाराष्ट्र की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां तेज-तर्रार अधिकारी खाद्य प्रशासन को मिला है। दूसरे इलाकों में ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में मिलावटखोरी बंद हो गई है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो कि शुद्ध खाना और दवा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। बिडंबना ही कहेंगे कि जिस मिलावटखोरी से हर साल देश में करीब दो लाख लोग मौत की भेंट चढ़ जाते हैं, फिर भी हमारी कानूनी तंत्र इस पर प्रभावी रोक लगाने में नाकाम रहा है। वैसे तो हर साल त्योहारी सीजन के साथ ही मिलावटखोरी की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन इन दिनों इस चर्चा की वजह महाराष्ट्र के तेजतर्रार आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे की कार्रवाई है। मुंढे ने जब से महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए के आयुक्त का पद संभाला है, मिलावटखोरों की शामत आ गई है। उन्होंने खाद्य कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। महाराष्ट्र एफडीए की टीमों ने शुरुआती 100 दिनों में ही 904 से यादा छापे मारकर 450 से अधिक मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया और करोड़ों के



मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए। इस कार्रवाई से महाराष्ट्र में डिटर्जेंट और रसायनों से बने नकली दूध और ताड़ के तेल से बनने वाले एनालॉग पनीर का रैकेट ध्वस्त हो गया है। नियमों और स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने वाले कई नामी फूड चेन्स, बड़े रेस्तराओं आदि के लाइसेंस तक निलंबित या रद्द किए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां तेज-तर्रार अधिकारी खाद्य प्रशासन को मिला है। दूसरे इलाकों में ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में मिलावटखोरी बंद हो गई है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो कि शुद्ध खाना और दवा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। ब्रिटेन और अमेरिका में ध्यान रखा जाता है कि उपभोक्ताओं तक वही सामान पहुंचे, जो शुद्ध है। ऐसी व्यवस्था भारत में भी की गई है। 2006 में संसद से पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई का गठन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत कार्यरत इस संस्था का दायित्व खाद्य पदार्थों के मानकों पर निगाह रखना और उन्हें तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। रायों की पुलिस, प्रशासन और आपूर्ति अधिकारियों को भी अधिकार है कि वे मिलावटखोरी रोकें। त्योहारी सीजन में ये संस्थाएं कार्रवाइयां करती भी हैं।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 से हर साल करीब एक लाख से अधिक खाद्य नमूनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर करीब आठ हजार से यादा खाद्य व्यावसायिक लाइसेंस रद्द भी किए गए हैं। लेकिन देश में इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका है। रोक ना लग पाने के पीछे मोटे तौर पर तीन कारण नजर आते हैं। पहला है, मुनाफाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति, दूसरा नैतिकता का क्षरण और तीसरा कारण निश्चित तौर पर प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार है।विनोबा भावे ने करीब आठ दशक पहले लिखे अपने निबंध 'नवयुवकों से दो बातें' में कहा है कि देश में सुराख ही सुराख हैं। उन्होंने राष्ट्ररूपी घड़े में बने इन सुराखों को सदाचार से भरने की अपील की है। कुछ उसी तरह व्यवस्था में अब भी सुराख हैं। हमारे तंत्र के बड़े हिस्से से सदाचार और कर्तव्यपराणयता गायब है। वह राष्ट्र निर्माण के भाव से दूर है। इस वजह से वक्त पर कार्रवाई नहीं होती। कई बार तंत्र को जानकारी होती है कि फलां कारोबारी आटे में पत्थर का सफेद बुरादा मिला रहा है, चावलों में प्लास्टिक के दाने फेंट रहा है, दवाओं के सैंपल में गड़बड़ी कर रहा है, नकली मावे की मिठाई बेच रहा है, जाली शराब बिक रही है। वक्त पर इन गड़बड़ियों की जानकारी होने के बावजूद मुनाफाखोर से मिलने वाली चंद रकम के एवज में वह चुप रह जाता है। भले ही नकली दूध पीने से नागरिक बीमार हो रहा हो या नकली शराब से निर्दोष जान जा रही हो। नैतिकता का क्षरण भी मिलावटखोरी के लिए जिम्मेदार है। नैतिकता की कमी मुनाफाखोर कारोबारी और उत्पादक के साथ तंत्र में भी पैठी हुई है।सत्ता संभालते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने तंत्र को चेताया था कि सब चलता है-वाली मानसिकता की अब गुंजाइश नहीं रही। शुरू में इससे ग्रस्त लोगों में भय दिखा, लेकिन अब तंत्र का बड़ा हिस्सा उसी पुराने ढर्रे पर चलता दिखता है, इसलिए मुनाफाखोरों और मिलावटखोरों का डर कम हो चला है। स्वास्थ्य संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस मामले में केंद्र के साथ राय सरकारों को भी कार्रवाई का अधिकार है। ऐसे में तंत्र को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए केंद्र और रायों की सरकारों को जीरो टालरेंस की नीति अख्तियार करना जरूरी लगता है। तभी मुनाफाखोर, मिलावटखोर और लापरवाह प्रशासनिक तंत्र के पेंच कसे जा सकते हैं।

टिकाऊ खेती आज की आवश्यकता

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?







जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन

भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.7 करोड़ को छू चुकी है जो 1991-2000 तक 1.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि में रही, जबकि खाद्यान्न उत्पादन 2003-04 में 213.5 मिलियन टन तक पहुंचा अर्थात् 2.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से.

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?

हमें आगे भी 21वीं सदी के बाद से खाद्यान्न में लगभग 25-30 प्रतिशत की वृद्धि कायम रखनी होगी अन्यथा पूरा देश हमारा सूखा घोषित हो जायेगा जिससे की लगभग 14 प्रतिशत उत्पादन में गिरावट होगी जो भविष्य के लिए प्रगति के उत्तम संकेत नहीं हैं.

भूमि-जल पर्यावरण

खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों शाकनाशियों अर्थात् रसायनों के अत्यधिक प्रयोग में भूमि की दशा निश्चय ही खराब हुई है. जिससे की भूमि के लाभदायक कीट, केंचुए, जीवाणु इत्यादि नष्ट हुए हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म तत्वों में भी भारी कमी हुई. अतः जीवांश खादों के प्रयोग से हम रोक सकते हैं फसल चक्र अपना सकते हैं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कर सकते हैं कई जंगल भी नष्ट किये गये सघन पद्धतियों के प्रयोग के कारण जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है अर्थात् इसका दोहन कम किया जाए एवं इन्हें संरक्षित किया जाने का प्रयास करना नितांत आवश्यक है.

लाभ/खर्च अनुपात

हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की उपलब्धि बनाये रखने के लिए सस्य रसायनों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है. जिससे की हमारी भूमि में मृदा में तथा मृदा के गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है. यदि यह प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रही तो भूमि एवं जल की उपादेयता समाप्त हो जायेगी और नई पीढ़ी का जीवन ही असुरक्षित हो जायेगा वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र बराबर कम होता जा रहा है. ऐसी परिस्थिति में हम टिकाऊ खेती का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है तथा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वर्तमान व भविष्य दोनों में संतुलन हो. इस प्रकार की खेती का प्रयोग करके हम अपने भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित तो कर रही है बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं सुरक्षा करके या उन्हें सुरक्षित बनाये रखने का कर्त्तव्य भी पूरी तरह निभा रहे हैं. अर्थात् हमें टिकाऊ खेती का प्रयोग किया जाना चाहिए. जिसके द्वारा हमें आर्थिक लाभ एवं भारत सरकार को पूर्णतः उत्पादन से लाभ प्राप्त हो सके.

कृषि क्षेत्र में सम्पन्नता लाने के लिए उत्पादकता टिकाऊपन तथा समानता की बहुत जरूरत है हमें भारत में भी बदलते पर्यावरण में कृषि निर्वाह की प्राथमिकता देनी अनिवार्य आवश्यकता है. इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में हम आर्थिक दृष्टि से कारगर, पर्यावरण की दृष्टि त्रुटीहीन सामयिक दृष्टि से सुसंगत प्रौद्योगिकी जो कम लागत पर अधिक से अधिक कृषि उत्पाद दे सकें.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टिकाऊ खेती मानव जाति को निरंतर खुशहाली प्रदान का वचन देती है.

टिकाऊ खेती का महत्व

टिकाऊ खेती का महत्व सबसे अधिक वर्तमान खेती की प्रणालियों, तरीकों एवं समस्याओं को सुधारने में है. टिकाऊ खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं मृदा, जल, ऊर्जा, वन-विकास एवं जंगली पशुओं की सुरक्षा या इन्हें सुरक्षित रखने से है. टिकाऊ खेती में इनके प्रबंधन पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है. कई प्रकार की उत्पन्न समस्याओं जैसे- सौर ऊर्जा का उचित प्रयोग, वातावरण प्रदूषण की रोकथाम पर्यावरण का संतुलन डगमगाना इत्यादि समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना ही इसमें निम्न विषय है अर्थात् भविष्य में टिकाऊ खेती के माध्यम से इन समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है.

टिकाऊ खेती का लाभः

- पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाये रखने में टिकाऊ खेती का प्रमुख कार्य है.
- वातावरणीय प्रदूषण कम होता है.
- लगाई फसलों की उत्पादन लागत कम आती है.
- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उचित प्रकार से करते हैं.

धनिया की उन्नत खेती

धनिया हमारे दैनिक उपयोग के मसालों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो पूरे वर्ष सम्पूर्ण देश में उगाया जाता है इसलिए पूरे वर्ष आय का साधन हो सकता है, हरी पत्तियां सब्जियों में उपयोग की जाती हैं। धनिया में मधुर सुगंध कोरोमिन्डाल, लिनाकोल, एल्कोहल पदार्थ उपस्थिति के कारण होता है। सूखे धनिया के बीजों को रबी में बोया जाता है। मध्यप्रदेश का 70 प्रतिशत धनिया गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, दतिया जिले में उगाया जाता है इसके अलावा शाजापुर, मंदसौर, राजगढ़ जिलों में भी बोया जाता है। अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण उपज के लिये उन्नत तकनीक अपनाना आवश्यक है।





भूमि

असिंचित धनिया के लिये काली मिट्टी जिसकी जलधारण क्षमता एवं जल निकास वाली अच्छी भूमि हो और सिंचित धनिया बोने के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है जिसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त हो।

खेत की तैयारी

असिंचित क्षेत्र में अंतिम वर्षा जल की नमी को संरक्षित करते हुए 2-3 जुताई कर यथाशीघ्र बुवाई करें तथा सिंचित खेत में खरीफ फसल की कटाई के बाद 2-3 जुताई करें।

बुवाई का समय

रबी में बुवाई के लिये 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक उपयुक्त समय है। देरी बुवाई करने पर भभूतिया रोग की संभावना बढ़ जाती है।

उन्नत जातियां

साधना,पंत हरितिमा, गुजरात धनिया, सिंधु,स्वाति, उदयपुर धनियां-20

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

खेत की तैयारी के समय 15-20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद खेत में मिला दें। सिंचित अवस्था में प्रति हेक्टर 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 किलोग्राम पोटाश पर्याप्त होता है। जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा आधार खाद के रूप में बुवाई के समय बीज के नीचे ऊर कर दें तथा शेष नत्रजन की मात्रा प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई के समय दें उस समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है।

बीज की मात्रा एवं बुवाई विधि

सिंचित अवस्था में बीज दर 12-15 किलो ग्राम तथा असिंचित अवस्था में 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। जिसे बुवाई पूर्व बीज को 24 घंटे पानी में भिगो कर रखें जिससे अंकुरण शीघ्र और अच्छा होता है। इसके बाद थाइरम या डाइथेम -एम 45 की 3 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज उपचारित कर बोयें। बुवाई कतारों में की जाती है जिसमें कतार से कतार की दूरी 25-30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेमी रखें और बीज को 3-5 सेमी गहराई पर बुवाई करें।

निंदाई एवं गुड़ाई

धनिये की फसल में प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई के 25-30 दिन पर करना चाहिये जिसमें जहां अधिक पौधे उगे हों वहां से पौधे उखाड़ दें।

सिंचाई

अच्छी पैदावार के लिये फसल की क्रान्तिक अवस्थायें - जैसे शाखायें फूटते समय, फूल आते समय, बीज बनते समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। सिंचाई 10-15 दिन के अंतराल पर करें जो मिट्टी की किस्म और मौसम पर निर्भर करता है।

फसल उत्पादन

धनिया की फसल बीज के लिये 140-150 दिन में तैयार हो जाती है। बीज के रूप में 15 से 20 क्विं. प्रति हेक्टर उत्पादन प्राप्त होता है। पत्तियों के रूप में बोने के 45 दिन पश्चात से पत्तियों की कटाई कर विक्रय किया जा सकता है।

धनिया कटाई के बाद प्रबंधन

- फसल अवधि पूर्ण होने के पश्चात जब दाने परिपक्व हो जाये एवं दाने हरे रहें तब उसे काटकर छायादार स्थान में सुखाना चाहिए। दाने हरे रंग के रहने से बाजार में अधिक कीमत मिलती



न्यूज इन शॉर्ट



सेवा संकल्प अभियान के तहत विकासखंड स्तरीय सेवा सेतु शिविर का आयोजन

एमसीबी सेवा संकल्प अभियान के तहत आमजन तक शासन की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और उनकी समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के जनपद पंचायत सभाकक्ष अमृत सदन में विकासखंड स्तरीय सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाद्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तथा राशनकार्ड से जुड़े कार्यों एवं प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को दी गई। शिविर की अध्यक्षता सहायक संचालक खाद्य विभाग हुलेश डडसेना ने की। इस अवसर पर जिला खाद्य अधिकारी विष्णुनारायण शुक्ला, खाद्य निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ भूपेंद्र राज, खाद्य निरीक्षक केल्हारी श्रीमती ममता भगत, विधायक प्रतिनिधि श्रीमती कन्याकुमारी सिंह, ग्राम पंचायत छिपछिपी एवं तेंदूडांड के सरपंच, नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ के पार्षद एवं एल्डरमैन, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

वन नेशन वन राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की दी जानकारी

शिविर में वन नेशन वन राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तथा राशन कार्ड में आवश्यक संशोधन एवं अन्य संबंधित कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पात्र हितग्राही शासन की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग्रामीणों को राशनकार्ड से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं, खाद्यान्न प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने में आने वाली सामान्य प्रक्रियाओं एवं आवश्यक मार्गदर्शन से अवगत कराया गया। सेवा संकल्प का संदेश-पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध पहुंचे योजनाओं का लाभ शिविर के दौरान सेवा संकल्प अभियान की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सहज, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनका निराकरण करना और जरूरतमंदों को सही योजना की जानकारी उपलब्ध कराना सेवा भावना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण

शिविर में उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को राशन वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा हितग्राहियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन में उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हितग्राहियों को राशन वितरण एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराते हुए शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग किया जाए। सेवा सेतु शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को खाद्य विभाग की योजनाओं की जानकारी, राशन कार्ड संबंधी प्रक्रियाओं की समझ और आवश्यक मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। इससे आमजन और विभाग के बीच संवाद का माध्यम मजबूत हुआ तथा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी पहल हुई।

पांच विभाग मिलकर बनाएंगे कार्ययोजना

सीएम ने ली समीक्षा बैठक:हादसे रोकने ब्लैक स्पॉट सुधारेंगे इलाज का सिस्टम भी होगा दुरुस्त

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

सड़क हादसे में मौत रोकने के लिए अब सिर्फ दुर्घटना वाले स्थानों को सुधारने तक सीमित नहीं रहा जाएगा। हादसा होने से पहले उसकी रोकथाम, दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने और वहां समय पर इलाज तक पूरी व्यवस्था को एक साथ मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा में 'जीरो फेटेलिटी' का लक्ष्य रखते हुए परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और नगरीय निकायों को मिलकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में राय के 23 ब्लैक स्पॉट पर सुधार की कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस जांच, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ई-ट्रैक के जरिए कंप्यूटराइड ड्राइविंग टेस्ट और लंबित ई-चालानों की वसूली की स्थिति भी देखी गई। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की सूचना से लेकर एंबुलेंस के पहुंचने और घायल को अस्पताल में उपचार मिलने तक विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया। वाहनों की फिटनेस जांच में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन स्थलों तक परिवहन कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ही दूरस्थ और परिवहन से वंचित इलाकों में नए बस मार्ग शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आरटीओ में रहेगा हर वाहन मालिक का मोबाइल नंबर

वाहन मालिक का मोबाइल नंबर बदल गया और आरटीओ के रिकॉर्ड में पुराना नंबर ही दर्ज है तो ई-चालान समेत वाहन से जुड़ी जरूरी सूचनाएं उस तक नहीं पहुंच पातीं। इस वजह से रायभर में 100 करोड़ से यादा का ई चालान पेंडिंग है। अब परिवहन विभाग इस समस्या को दूर करने के लिए सारथी एप में मोबाइल नंबर खुद अपडेट करने की व्यवस्था तैयार कर रहा है।

इसमें वाहन मालिक को मोबाइल नंबर बदलने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह ऑनलाइन अपना नया नंबर अपडेट कर सकेगा और यह नंबर सीधे परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। यह सुविधा सिर्फ पुराने नंबर को बदलने तक सीमित नहीं होगी। वाहन बिकने के बाद नए मालिक का मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट किया जा सकेगा। अभी

ग्रामीण इलाकों में चलेंगी बसें, 10 करोड़ करेंगे खर्च



मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बस्तर-सरगुजा में अभी 13 जिलों के 106 मार्गों पर 107 बसें चल रही हैं। इन बसों के संचालन पर करीब 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं।

एनआरसी का कमाल कोरबा के नन्हें आकाश ने जीती कुपोषण से जंग

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

कुपोषण के शिकार बच्चों को समय पर उपचार, पौष्टिक आहार और विशेष देखभाल देकर उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर वापस लौटने में मदद कर रहे हैं। पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की निगरानी और नियमित फॉलोअप किया जाता है। बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर कर उन्हें स्वस्थ जीवन देने में पोषण पुनर्वास केंद्र (ह्रञ्ष्ट) वरदान साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ के कोरबा जिले के कोरबा जिला चिकित्सालय स्थित एनआरसी जीएमसी की बेहतरीन देखरेख और चिकित्सीय सहायता से नवधापारा (मुड़ापार) निवासी श्रीमती राधिका महंत के 18 माह के बेटे आकाश ने कुपोषण को मात देकर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाए हैं।

'कमजोरी और बीमारी से थी परेशानी'

श्रीमती राधिका ने बताया कि कुछ समय पहले उनका बेटा आकाश लगातार कमजोर होता जा रहा था।



उसका वजन कम होने के साथ उसे बार-बार तेज बुखार आता था, जिससे वह काफी चिड़चिड़ा रहने लगा था। सीमित आर्थिक स्थिति के कारण निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराना परिवार के लिए असंभव था। ऐसे में मितानिन और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद से उसे जिला चिकित्सालय लाया गया।

'मिला आर्थिक संबल'

उपचार और पौष्टिक आहार के साथ-साथ योजना के तहत राधिका को 2,200 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की गई, जिससे इलाज से जुड़े खर्चों की चिंता दूर हुई। इस सफलता से गदगद राधिका महंत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अन्य अभिभावकों से भी अपील की है कि बचों के स्वास्थ्य में कमजोरी दिखने पर समय पर एनआरसी की मदद लें।

लखपति दीदी डोंगरगढ़ की दिनेश्वरी सोरी ने बिहान योजना से बदली तकदीर

मशरूम उत्पादन से लेकर अगरबत्ती, साबुन और गोबर के दीये निर्माण तक कई आजीविका गतिविधियों से बढ़ाई आय

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में स्वसहायता समूह किस प्रकार मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड स्थित ग्राम धनडोंगरी की लखपति दीदी श्रीमती दिनेश्वरी सोरी ने पेश की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़कर उन्होंने सामान्य गृहिणी से लेकर एक सफल स्वरोजगार संचालक बनने का सफर तय किया है।

'समूह के सहयोग से शुरू किया कारोबार'

श्रीमती दिनेश्वरी सोरी 'जय सेवा जय बूढ़ा देव स्वसहायता समूह' से जुड़ीं। शुरुआती दौर में पूंजी की कमी उनके सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन समूह और ग्राम संगठन से मिले वित्तीय सहयोग ने उनकी राह आसान कर दी। समूह से प्राप्त ऋण और अनुदान की मदद से उन्होंने अगरबत्ती बनाने की मशीन खरीदी और व्यवस्थित उत्पादन शुरू किया। इसके बाद बैंक से एक लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण लेकर उन्होंने अपने कारोबार का और विस्तार किया।

'इन उत्पादों से हो रही है बंपर कमाई'

स्थानीय बाजार की मांग और अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सोरी ने कई आजीविका गतिविधियों को एक साथ अपनाया है। वर्तमान में वे मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती और साबुन निर्माण, निरमा, गुलाल और मोमबत्ती, गोबर के दीये और चूड़ी निर्माण संबंधी उत्पादों का निर्माण कर रही हैं।

'वार्षिक आय हुई डेढ़ लाख रुपये'

बिहान योजना से जुड़ने से पहले उनका परिवार मुख्य रूप से कृषि और मजदूरी पर निर्भर था, जिससे वार्षिक पारिवारिक आय महज 52 हजार रुपये थी। लेकिन स्वरोजगार के नए साधन विकसित होने से अब उनकी वार्षिक आय बढ़कर लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये हो गई है। नियमित आमदनी होने से न केवल परिवार की दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं, बल्कि आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत हुई है। श्रीमती दिनेश्वरी की यह सफलता आज ग्रामीण इलाके की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने और मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।

राजनांदगांव की कुमारी बाई के जीवन में स्वछ भारत मिशन से आया सकारात्मक बदलाव

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

स्वछ भारत मिशन ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा का एक नया अध्याय लिख रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लक्ष्मणभरदा निवासी श्रीमती कुमारी बाई के परिवार के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। घर में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण से उनके परिवार को खुले में शौच की समस्या से मुक्ति मिली है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण प्राप्त हुआ है।

प्रक्रिया और वित्तीय सहायता'

ग्राम पंचायत लक्ष्मणभरदा में जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ग्रामसभा से अनुमोदन और सत्यापन के बाद पात्र हितग्राहियों के लिए शौचालय निर्माण स्वीकृत किए गए। इसी कड़ी में श्रीमती कुमारी बाई का चयन किया गया और उनके परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद परिवार को इसके नियमित



उपयोग और साफ-सफाई के प्रति भी जागरूक किया गया।

'बदली दिनचर्या और घटे चिकित्सीय खर्च'

घर में शौचालय बन जाने से परिवार की दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है। अब परिवार के सदस्यों को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। श्रीमती कुमारी बाई ने बताया कि स्वछ वातावरण मिलने से बचों में दस्त और अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका कम हुई है, जिससे दवाइयों और इलाज पर होने वाले खर्च में भी खासी कमी आई है।

VB-G-RAM-G के तहत VGPP 2027-28 की तैयारी को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित



मास्टर ट्रेनर्स ने लाइव डेमो के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया समझाई

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी



जिला पंचायत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में के अंतर्गत वर्ष 2027-28 के लिए तैयार किए जाने को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला स्तर के विभिन्न विभागीय एजेंसियों के अधिकारी एवं कर्मचारी, जनपद पंचायतों से ड्डक्रत-ब्रारूत्र के कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, सहायक प्रोग्रामर तथा सृजन की टीम के सदस्य शामिल हुए।

कार्यशाला का उद्देश्य आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जाने वाली विकास योजना को निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं राय की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया को समझाना तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना रहा।

कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ड्डक्रत्रक्क तैयार करने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान योजना निर्माण की प्रक्रिया, आवश्यक प्रविष्टियां, प्राथमिकताओं का निर्धारण, उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप योजना तैयार करने की प्रक्रिया को समझाया गया।

प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा लाइव डेमो के माध्यम से ड्डक्रत्रक्क तैयार करने की पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित की गई। प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रक्रिया में आवश्यक जानकारी दर्ज करने, विभिन्न चरणों को पूरा करने तथा योजना तैयार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर प्रश्न एवं जिज्ञासाएं रखी गईं, जिनका मास्टर ट्रेनर्स द्वारा समाधान किया गया। प्रतिभागियों को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर तक प्रभावी रूप से करते हुए निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ड्डक्रत्रक्क तैयार करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

जिला स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से ड्डक्रत-ब्रारूत्र के अंतर्गत आगामी वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को अधिक व्यवस्थित, आवश्यकता आधारित और राय की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने की दिशा में अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

नई शुरुआत

भारत सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में स्टेट लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (ह्रञ्ष्ट) द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

बैठक में प्रस्तावित परियोजना के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मास्टर प्लान, भूमि



उपलब्धता, आवश्यक अधोसंरचना, परियोजना लागत, वित्तीय व्यवस्था तथा की संचालन गाइडलाइन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

'नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित है औद्योगिक पार्क'

प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। लगभग 406.72 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस औद्योगिक पार्क में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

'भारत सरकार को भेजा जाएगा परियोजना प्रस्ताव'

स्टेट लेवल कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे भारत सरकार को भेजे जाने के लिए अनुमोदित किया गया है। अब ब्क्र।, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।